॥ 卐 ॥

THURSDAY » न्यायालय के आलोक में बेटी का अधिकार 4 » कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला 7 » भारत बनाम न्यूजीलैंड ऑल-फॉर्मेट सीरीज का ऐलान, रोहित-कोहली की मैदान पर वापसी 6

दिनमान | तापमान
सूर्योदय 4.51 सूर्यास्त 6.18 | अधिकतम 37° न्यूनतम 29°

वर्ष 18, अंक 347 पृष्ठ 8
कोलकाता, गुरुवार, 4 जून 2026
ज्येष्ठ, कृष्णपक्ष, चतुर्थी, वि.सं. 2083

मूल्य: ₹ 3

निष्पक्ष, निडर एवं सशक्त राष्ट्रीय दैनिक

युवा शक्ति

कोलकाता संस्करण www.yuvashaktinews.com

ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल में बड़ी टूट

बागी गुट ने ऋतब्रत को चुना नेता विपक्ष ■ दीदी को मुख्य सलाहकार पद का प्रस्ताव ■ बागी 58 विधायकों को स्पीकर की मंजूरी ■ अभिषेक की कार्यशैली पर उठाए सवाल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी में टूट हो गई है. पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी समेत 58 बागी नेताओं को विधानसभा स्पीकर ने मंजूर दे दी है. स्पीकर ने ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी. ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों ने स्पीकर रवीन्द्र नाथ बोस से मुलाकात कर उनसे कहा था कि वे टीएमस के असली गुट हैं और ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी जाए. वैसे, चुनावों में हार के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने शुरू में बालीगंज से विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विधायक दल का नेता चुना था. इसके बाद, पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव ने विधानसभा को एक पत्र भेजा.

इस पत्र में आधिकारिक फैसला बताया गया और अनुरोध किया गया कि शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी जाए. हालांकि, जल्द ही उस पत्र पर हस्ताक्षर की जालसाजी के आरोप सामने आए. सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की. जांच अधिकारी कई विधायकों के घरों पर गए, और अभिषेक बनर्जी को भी नोटिस दिया गया. इस बदलते हालात के बीच, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तृणमूल के दो विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने हस्ताक्षर की जालसाजी का मामला सामने लाया था. इसके तुरंत बाद, तृणमूल कांग्रेस ने इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया.

इन घटनाओं के बाद, हालात और भी मुश्किल हो गए. ऐसी खबरें आईं थी कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ही बगावत हो रही है. चर्चा थी कि कम से कम 50 विधायक ऋतब्रत के साथ मिल गए हैं. हाल के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटें जीती थीं. दलबदल विरोधी कानून के नियमों को दरकिनार करने के लिए, ऋतब्रत और उनके गुट को कम से कम 53 विधायक के समर्थन की ज़रूरत होती. लेकिन, बुधवार सुबह यह साफ़ हो गया कि उनकी संख्या उस लिमिट से काफ़ी ज़्यादा थी. आज विधानसभा में हुई मीटिंग में जिसमें ऋतब्रत को विधायक दल का नेता चुना गया. 59 विधायकों के हस्ताक्षर हैं. स्पीकर को दिए गए पत्र में कहा गया था कि बाद में छह और सदस्य हस्ताक्षर करेंगे.

इसके अलावा, स्पीकर के सामने खड़े होकर, बागी तृणमूल विधायकों ने ऑफिशियली ऐलान किया कि उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुना है. वहीं जावेद खान, संदीपन साहा और शिउली साहा को उप नेता चुना गया, जबकि अखरुज़्ज़मां को विपक्षी पार्टी का चीफ़ व्हिप चुना गया. खास बात यह है कि डॉक्यूमेंट में ममता बनर्जी को अपना सुप्रीम लीडर बताया गया.

ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि उनका गुट ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इस गुट के दल का मुख्य सलाहकार बनने का अनुरोध करेगा. उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ममता बनर्जी पार्टी को मार्गदर्शन देती रहें. दूसरी तरफ निष्कासित टीएमसी नेता संदीपन साहा ने भी दावा किया कि नेता विपक्ष का कमरा आधिकारिक तौर पर आवंटित हो चुका है. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बागी गुट अब खुद को विधानसभा के अंदर असली टीएमसी विधायक दल के रूप में पेश कर रहा है. ऋतब्रत ने यह भी कहा कि

मैंने पार्टी में बात करने की कोशिश की तो पहले तीन दिन तो मुझे घुसने ही नहीं दिया गया. भ्रष्टाचार इस चुनाव का अहम मुद्दा रहा. बार-बार बोलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सबूत थे. फिर बोला गया कि चुनाव के बाद कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. अभिषेक बनर्जी चोरों की तरह पिटने के बाद बोले कि आवाम उनकी सुरक्षा करेगी. फिर उनकी तरफ से सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखी गई.

टीएमसी के भीतर अब खुलकर दो धड़े दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का आधिकारिक गुट है, जबकि दूसरी तरफ बागी विधायक हैं जो खुद को असली विधायक दल बता रहे हैं. ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि उनके साथ 58 विधायक हैं और दो अन्य विधायक भी जल्द जुड़ सकते हैं. संदीपन साहा ने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली को पार्टी की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार बताया. उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता सफलता का श्रेय लेता है तो उसे हार और संकट की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए. इससे पहले भी कई बागी नेता अभिषेक बनर्जी की रणनीति और संगठन संचालन पर सवाल उठा चुके हैं.

बागी गुट के विधायक दल में किसको क्या जिम्मेदारी मिली?

पद	नाम
नेता विधायक दल	ऋतब्रत बनर्जी
चीफ व्हिप	अखरुज्जमान
उपनेता	जावेद अहमद खान
उपनेता	संदीपन साहा
उपनेता	सबीना यास्मीन
उपनेता	शिउली साहा

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बागी गुट के दावों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि निष्कासित विधायक नेता विपक्ष नहीं बन सकते. कुणाल घोष ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग पत्र दिए गए हैं और कई विधायकों के हस्ताक्षर दोनों पत्रों में हैं. उन्होंने कहा कि मामले की कानूनी और संसदीय जांच होगी और अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा.

माना जा रहा है कि अगर बागी गुट मजबूत होता है तो बंगाल विधानसभा के अंदर शक्ति संतुलन बदल सकता है. टीएमसी के भीतर यह टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है. भाजपा भी इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है और इसे टीएमसी की अंदरूनी कमजोरी के तौर पर देख रही है.

फिरहाद हकीम का कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस को बुधवार को एक और बड़ा झटका लगा. पार्टी सूत्रों के अनुसार, कोलकाता नगर निगम के मेयर और राज्य के पूर्व मंत्री फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. तृणमूल विधायक कुणाल घोष ने बताया कि फिरहाद हाकिम ने तृणमूल प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुमति लेने के बाद यह फैसला किया है. उनके अनुसार, फिरहाद ने ममता बनर्जी को बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में नगर निगम में प्रभावी ढंग से काम करना संभव नहीं हो पा रहा है. पहले ममता बनर्जी ने उन्हें ऐसा कदम उठाने से मना किया था, लेकिन बाद में उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इस्तीफे की अनुमति दे दी.बुधवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में नवान्न में आयोजित प्रशासनिक समीक्षा बैठक में शामिल होने वाले तृणमूल नेताओं में फिरहाद हकीम भी शामिल थे. बताया जा रहा है कि बैठक से लौटने के बाद उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा सौंप दिया.

फिरहाद हाकिम नवंबर, 2018 में कोलकाता के मेयर बने थे. उस समय वह राज्य के शहरी विकास मंत्री भी थे. वह कोलकाता नगर निगम के इतिहास में पहले मुस्लिम मेयर बने थे. वर्ष 2021 में उन्होंने दूसरी बार मेयर पद की जिम्मेदारी संभाली. लगभग आठ वर्षों तक मंत्री और मेयर दोनों पदों की जिम्मेदारी निभाने के बाद उनका इस्तीफा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.इससे एक दिन पहले नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य (निकासी) तारक सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफे के बाद उन्होंने तृणमूल नेतृत्व की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दे रही है. उन्होंने भविष्य में तृणमूल के चुनाव चिह्न पर चुनाव नहीं लड़ने की भी घोषणा की थी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा की थी.तारक सिंह के इस्तीफे के बाद फिरहाद हकीम ने कहा था कि नगर निगम की टीम एकजुट होकर काम करती है और सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं. ऐसे में अगले ही दिन उनका इस्तीफा सामने आना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.हकीम का इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है जब राज्यभर में टीएमसी के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने पद छोड़ चुके हैं और संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिशें चल रही हैं.

दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड

विदेशी नागरिकों समेत 21 की मौत

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की एक तंग गली में स्थित एक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई. इनमें वे विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनके बीमार रिश्तेदारों का पास के अस्पतालों में इलाज चल रहा था. मालवीय नगर के हौज रानी स्थित 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' में सुबह करीब 8:30 बजे आग लगी और देखते ही देखते फैल गई, जिससे लोग स्तब्ध रह गए. कई स्थानीय लोगों सहित बचावकर्मी पांच मंजिला संकरी इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि लगभग 40 लोगों को इमारत से निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. कई घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार की 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' नीति के तहत होटल को केवल छह कमरों की अनुमति थी, लेकिन वह 25 कमरे का उपयोग कर रहा था. तहखाने में भी कमरे बनाए गए थे.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि होटल में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही द्वार था. मृतकों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें से कई मध्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के हैं. उनके परिजनों का इलाज कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित मैक्स अस्पताल में चल रहा था, जिस वजह से वे होटल में ठहरे हुए थे.

इलाके से मिले दृश्यों में संकरी गलियां, लटकते तार और तंग इमारतें बेतरतीब ढंग से एक-दूसरे से सटी हुई दिखाई दे रही हैं. इनमें हवा में उठती आग की ऊंची लपटें भी दिख रही हैं. इमारत के चारों ओर कांच बिखरा पड़ा था.

दिल्ली अग्निशमन सेवा, पुलिस और आपदा राहत इकाइयों की टीमों ने धुएं से काली पड़ी इमारत में जीवित बचे लोगों की तलाश की. पीड़ितों को तहखाने से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से अस्पतालों में ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि आग 'लेमन ग्रीन रेस्तरां' में लगी थी, लेकिन पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि यह एक होटल की इमारत है. अग्निशमन अधिकारी ए. के. मलिक के अनुसार, इमारत में एक तहखाना, भूतल और पांच ऊपरी मंजिलें हैं. रेस्तरां भूतल पर था जबकि इमारत के बाकी हिस्से का उपयोग होटल के रूप में किया जा रहा था.एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए इमारत की तीसरी मंजिल से कूद गई. व्यक्ति ने बताया, इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा नीचे सड़क पर गद्दे बिछाए गए और एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए तीसरी मंजिल से कूद गई.

महिला अपने बच्चे के साथ एक गद्दे पर गिरी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. गद्दे बेचने वाले ने ज़मीन पर गद्दे बिछा दिए ताकि इमारत से जान बचाने की कोशिश में कूदने वाले लोगों को चोट न लगे, जबकि अन्य लोगों ने घायलों को सीपीआर दिया.सड़क के उस पार स्थित मैक्स अस्पताल में, स्तब्ध रिश्तेदार अपने प्रियजनों की तलाश में प्रतीक्षा क्षेत्र में जमा हो गए, घायल और मृतकों को लाए जाने पर सूचियों को खंगालते रहे और घबराकर फोन करते रहे.

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पहुंची. ईडी अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी को समन सौंपने के लिए उनके घर पहुंचे थे. हालांकि, मामले को लेकर ईडी की ओर से विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन समन सौंपने की कार्रवाई को लेकर बंगाल की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है. अभिषेक बनर्जी पहले भी कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर चुके हैं. वहीं सभी की नजर इस बात पर है कि समन मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी का अगला कदम क्या होगा और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है. बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर पूछताछ के लिए समन भेजा.यह घोटाला 2016 में बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है.

डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री

कैबिनेट में सिद्धारमैया के बेटे समेत 13 मंत्री शामिल

बेंगलुरु : कर्नाटक में बुधवार को डी. के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र और पिछली सरकार के 11 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उपस्थिति में, शिवकुमार ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर संत गंगाधर अज्जा के नाम से शपथ ली. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने लोक भवन में शिवकुमार, परमेश्वर और अन्य विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी यतींद्र को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है. हालांकि, मंत्रिमंडल गठन के पहले चरण में किसी भी महिला प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया. यतींद्र और यू. टी. खादर ही मंत्रिमंडल में नए चेहर हैं, बाकी सभी मंत्री वही हैं जो पिछली सरकार में भी थे. शपथ लेने वाले वरिष्ठ दलित विधायक जी. परमेश्वर को जल्द ही उप मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाएगा.

अन्य जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें के एच मुनियप्पा, के जे जॉर्ज, एम बी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बायरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, यू टी खादर, ईश्वर खंड्रे, यतींद्र सिद्धारमैया, बायराथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल शामिल हैं. कांग्रेस के एक नेता ने कहा, इस नए मंत्रिमंडल को देखकर ऐसा लग सकता है कि इस पर सिद्धारमैया की छाप स्पष्ट है. हालांकि, इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि मंत्रिमंडल गठन के अगले चरण में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है. मुख्यमंत्री सहित कर्नाटक के मंत्रिमंडल की स्वीकृत संख्या 34 है.

जातिगत संरचना की बात करें तो, मंत्रिमंडल में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वोक्कालिगा (शिवकुमार और रामलिंगा रेड्डी सहित) और वीरशैव-लिंगायत समुदायों से तीन-तीन मंत्रियों के साथ-साथ दलित मंत्रियों की भी समान संख्या है. सिद्धारमैया जिस कुरुबा समुदाय से संबंध रखते हैं, उससे दो मंत्री हैं; अनुसूचित जनजाति, ईसाई और मुस्लिम समुदायों से एक-एक मंत्री हैं. जिलावार प्रतिनिधित्व देखें तो सबसे अधिक चार मंत्री बेंगलुरु शहरी से, दो कलबुर्गी से और एक-एक बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु ग्रामीण, तुमकुरु, विजयपुरा, बीदर, दक्षिण कन्नड़, बेलगावी और मैसूर जिलों से हैं. यतींद्र सिद्धारमैया एकमात्र एमएलसी हैं जिन्हें मंत्री पद मिला है, बाकी सभी विधायक हैं.

बंगाल में 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना शुरू

28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में तीन-तीन हजार रुपये ट्रांसफर

कोलकाता: बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली नवगठित भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के एक माह के भीतर राज्य में महिलाओं के लिए 3,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता वाली 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना की बुधवार को औपचारिक शुरुआत कर दी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इसका वादा किया था. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित कार्यक्रम में योजना की औपचारिक शुरुआत की.

योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से पांच लाभार्थी महिलाओं को चेक प्रदान किया. साथ ही इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से 28 लाख 25 हजार 769 महिला लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में तीन-तीन हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अगले तीन महीने तक जारी रहेगी. राज्य सरकार पात्र महिलाओं के पंजीकरण में हरसंभव सहायता प्रदान करेगी ताकि कोई भी योग्य लाभार्थी योजना से वंचित न रहे.

राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने बताया कि पहले लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ प्राप्त कर रही महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना के लिए नया पंजीकरण कराना होगा. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लक्ष्मी भंडार योजना के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए नए सिरे से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं.उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लगभग 2.2 करोड़ लाभार्थी दर्ज थे. राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी. यदि किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ मिलता हुआ पाया जाता है, तो आम नागरिकों को उस पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा. राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा योजना में पंजीकरण के लिए 12 पृष्ठों का आवेदन पत्र तैयार किया है. सरकार का दावा है कि इससे पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होगी और योजना का लाभ केवल योग्य महिलाओं तक पहुंचेगा.

मकान पर कब्जे के आरोप में तृणमूल प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार गिरफ्तार

कोलकाता: बंगाल में रसूखदार नेताओं द्वारा आम जनता की संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है. ताजा और बेहद हाई-प्रोफाइल मामला कोलकाता के वीआईपी इलाके साल्टलेक से सामने आया है, जहां बुधवार दोपहर को भारी हंगामे और जनता के आक्रोश के बाद तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.जयप्रकाश मजूमदार पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता और राजनीतिक रसूख के दम पर साल्टलेक के ब्लॉक-ई के मकान नंबर 337 को पिछले 12 से 14 सालों से अवैध रूप से दबा रखा था और उसे खाली नहीं कर रहे थे. बुधवार सुबह विवाद उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब फ्लैट में ताला लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. इस दौरान मकान की वर्तमान मालकिन आरती रायचौधरी (जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है) ने सड़क पर ही जयप्रकाश मजूमदार को रोक लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

देखते ही देखते स्थानीय निवासी भी बुजुर्ग महिला के समर्थन में उतर आए. गुस्साए लोगों ने जयप्रकाश मजूमदार की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी कार की चाबी छीन ली. इस दौरान भीड़ ने टीएमसी नेता को देखते ही 'चोर-चोर' के नारे लगाने शुरू कर दिए. कार के भीतर निरुपाय बैठे जयप्रकाश मजूमदार ने भीड़ को देखकर मौखिक रूप से घर खाली करने का आश्वासन दिया, लेकिन स्थानीय लोग लिखित गारंटी और तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. शिकायत के अनुसार, जयप्रकाश मजूमदार ने साल 2014 में नाममात्र के किराए पर साल्टलेक का यह घर सपरिवार रहने के लिए लिया था. बाद में उन्होंने इस मकान को खाली करने के बजाय इसे अपना दफ्तर बना लिया. मृत मकान मालिक की पत्नी आरती रायचौधरी का आरोप है कि जब भी वह टीएमसी नेता से अपना बकाया किराया मांगती थीं या घर खाली करने को कहती थीं, तो जयप्रकाश मजूमदार अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते थे. कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद भी उन्होंने घर नहीं छोड़ा. पुलिस के अनुसार, इस पूरे भूमि और फ्लैट विवाद के बीच मकान मालकिन के साथ बदसलूकी और चेश्रर्शीीरींळेप की धाराएं भी शिकायत में जोड़ी गई हैं. कुछ दिन पहले जब महिला स्थानीय लोगों को साथ लेकर अपना घर वापस लेने गई थी, तब भी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसका एक वीडियो (जिसमें जयप्रकाश मजूमदार की पत्नी को थप्पड़ मारे जाने की बात कही जा रही है) सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

आज दोपहर साल्टलेक में तनाव बढ़ता देख बिधाननगर उत्तर थाने की भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस पहले जयप्रकाश मजूमदार और शिकायतकर्ता महिला को थाने ले गई, जहां लंबी पूछताछ और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.

फांसीदेवा में राजनीतिक हलचल, नौ सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा

सिलीगुड़ी : फांसीदेवा पंचायत समिति में बुधवार को उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई, जब नौ सदस्यों ने मिलकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (नो कॉन्फिडेंस मोशन) जमा कर दिया. यह प्रस्ताव सिलीगुड़ी के एसडीओ कार्यालय में सौंपा गया, जिसके बाद स्थानीय राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. 21 सदस्य फांसीदेवा पंचायत समिति में वर्तमान में 18 सदस्य तृणमूल कांग्रेस, दो भाजपा और एक निर्दलीय (जो बाद में तृणमूल में शामिल हुए) है. ऐसे में नौ सदस्यों द्वारा एक साथ अविश्वास प्रस्ताव लाना मौजूदा समीकरण को बदलने का संकेत दे रहा है.पंचायत समिति के खाद्य कर्माध्यक्ष प्रणबेश मंडल ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ सदस्यों के व्यवहार के कारण विकास कार्यों में बाधा आ रही थी. इसी वजह से उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अध्यक्ष के खिलाफ यह प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होंगे या नहीं.वहीं, पंचायत समिति की अध्यक्ष रीना एक्का ने कहा कि उन्हें इस अविश्वास प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने हमेशा सभी सदस्यों के साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है. साथ ही, तृणमूल के संगठनात्मक नेतृत्व को भी इस मुद्दे की जानकारी नहीं होने की बात कही गई है.सिलीगुड़ी के महकमा शासक विकास रूहेला ने अविश्वास प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है. अब इस पर आगे की प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी है.

अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत रिषड़ा में 100 लाभार्थियों को मिला योग्यता प्रमाण पत्र

हुगली : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना की औपचारिक शुरुआत कर दी.

इस योजना के तहत राज्य की योग्य महिलाओं को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी. योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा घरेलू खर्चों एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है.

इसी क्रम में रिषड़ा के रवींद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में अन्नपूर्णा भंडार योजना के 100 लाभार्थियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए. कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि सभी

योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में शीघ्र ही योजना के तहत निर्धारित सहायता राशि भेजी जाएगी.इस अवसर पर रिषड़ा नगरपालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा, वाइस चेयरमैन जाहिद हसन खान, पार्षद शशि सिंह झा, पार्षद मनोज सिंह, पार्षद सुख सागर मिश्रा, नगरपालिका के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर सहित अन्य अधिकारी एवं पार्षदगण उपस्थित रहे.वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है. अन्नपूर्णा भंडार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है,

जिससे महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा.

सड़क हादसे में 10 लोग घायल, इलाके में हड़कंप

हुगली : अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी एक भुटभुटी (स्थानीय वाहन) के सड़क दुर्घटना का शिकार होने से 10 लोग घायल हो गए. यह हादसा हुगली जिले के गोघाट थाना अंतर्गत के हाजीपुर काठगोला इलाके में हुआ. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बुधवार को कुछ लोग एक मृतक के अंतिम संस्कार के लिए भुटभुटी वाहन से जा रहे थे. इसी दौरान हाजीपुर काठगोला इलाके में वाहन की एक पिकअप वैन से आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि भुटभुटी में सवार 10 लोग घायल हो गए. दुर्घटना की सूचना पाकर गोघाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है तृणमूल : खगेन मुर्मू

सिलीगुड़ी : भारतीय जनता पार्टी के सांसद खगेन मुर्मू ने तृणमूल कांग्रेस में जारी खींचतान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है. रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू बुधवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का जनाधार पहले ही खत्म हो चुका है. उन्होंने दावा किया कि राज्य के लोग लंबे समय से बदलाव चाहते थे, क्योंकि वे सरकार से निराश और वंचित महसूस कर रहे थे.उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्य गंभीर घटनाओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते जनता, खासकर युवा और महिलाओं ने बदलाव का फैसला किया.उन्होंने यह भी कहा कि ङ्गनया तृणमूलङ्ग ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है और पार्टी धीरे-धीरे टूट रही है.उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में तृणमूल में सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ही रह जाएंगे.वहीं, तृणमूल के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए खगेन मुर्मू ने कहा कि ङ्गजो भी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में शामिल है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. एक भी दोषी बच नहीं पाएगा.ङ्ग उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट रुख अपना चुके हैं.

कृष्णनगर में अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने वापस पाया अपना खोया हुआ पार्टी कार्यालय

दशगात्र :एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कांग्रेस ने कृष्णनगर बस स्टैंड के पास स्थित अपने पार्टी कार्यालय को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया है. कांग्रेस का आरोप है कि साल 2017 में सत्ता के बल पर और लाठी की राजनीति के दम पर तृणमूल कांग्रेस ने इस कार्यालय पर जबरन कब्जा कर लिया था. अंततः नदिया जिला अदालत के फैसले की कॉपी हाथ में लेकर, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कांग्रेस नेतृत्व ने इस कार्यालय को दोबारा हासिल किया.कार्यालय की बहाली के बाद नदिया जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता ने अदालत की डिक्री (आदेश) और आवश्यक दस्तावेज मीडिया के सामने पेश किए. उन्होंने बताया कि साल 2014 में कृष्णनगर नगरपालिका के पास पार्टी कार्यालय के लिए आवेदन किया गया था. तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर सिंह और नगरपालिका के संयुक्त प्रयासों से कृष्णनगर म्युनिसिपल काउंसिल ने इस आवेदन को मंजूरी दी थी और कांग्रेस को यह जमीन 99 साल की लीज पर दी गई थी. लीज मिलने के बाद पार्टी के तत्कालीन सामान्य सदस्यों और कार्यकर्ताओं के आर्थिक सहयोग से इस सुंदर कार्यालय का निर्माण किया गया था. इस कार्यालय के उद्घाटन के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सोमेन मित्रा और नगरपालिका के तत्कालीन चेयरमैन उदय मित्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिसकी पट्टिका (नेमप्लेट) आज भी कार्यालय की दीवार पर लगी हुई है.उन्होंने आगे आरोप लगाया, '2017 में तृणमूल की 'हार्माद वाहिनी' (गुंडों) ने बाहुबल के दम पर हमारे इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया था.

हम बार-बार प्रशासन के पास गए, थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की.' आखिरकार कोई रास्ता न देख कांग्रेस की ओर से कृष्णनगर मुंसिफ कोर्ट में बेदखली का मामला दर्ज कराया गया. लंबी सुनवाई के बाद साल 2023 में अदालत ने कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया और अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने का नोटिस जारी किया.अदालत का फैसला 2023 में आने के बावजूद इसे लागू होने में 3 साल का समय क्यों लगाङ्गइस सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता ने बताया कि कोर्ट का आदेश होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन और तृणमूल के एक वर्ग द्वारा पैदा की गई बाधाओं के कारण इस बहाली प्रक्रिया में देरी हुई. आखिरकार आज नदिया जिले के सभी स्तरों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यालय को वापस पा लिया.कांग्रेस नेतृत्व की ओर से बताया गया है कि आने वाले दिनों में इसी कार्यालय से नदिया जिले में कांग्रेस के सभी दलीय कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा. आम जनता तक पहुँचने के लक्ष्य के साथ, यहाँ से पहले कार्यक्रम के रूप में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के अलावा दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व के भी उपस्थित रहने की संभावना है.

बीरभूम में तृणमूल कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

बीरभूम: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की घटना सामने आई है. बोलपुर थाना अंतर्गत बाहिरी पांचशोया ग्राम पंचायत के बाहिरी पूर्वपाड़ा गांव में एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का आरोप बदमाशों पर लगा है. मृतक की पहचान हाबल लोहार (48) के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और सनसनी का माहौल है.स्थानीय लोगों और परिजनों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार देर रात हथियारों से लैस कुछ लोग हाबल लोहार के घर पहुंचे. परिवार का आरोप है कि हमलावर भाजपा समर्थक के रूप में जाने जाते हैं. लाठी, लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से लैस हमलावरों ने हाबल लोहार पर अचानक हमला कर दिया और उनकी बेरहमी से पिटाई की.परिजनों का दावा है कि हमलावरों की बर्बर मारपीट से हाबल लोहार गंभीर रूप से घायल होकर घटनास्थल पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़े. बाद में उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सक उन्हें बचा नहीं सके. परिवार का आरोप है कि मारपीट के कारण ही उनकी मौत हुई.घटना की सूचना मिलते ही बोलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व का आरोप है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके सक्रिय कार्यकर्ता की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है. वहीं भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप में प्रदर्शन

हुगली : श्रीरामपुर के तारापुकुर इलाके में सरकारी जलाशय (वेटलैंड) को भरकर अवैध निर्माण किए जाने के आरोप में स्थानीय निवासियों ने बुधवार को विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जलाशय को भरकर जमीन की बिक्री किए जाने से इलाके की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है और थोड़ी सी बारिश में भी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है.

प्रदर्शनकारियों ने 27 नंबर वार्ड के पार्षद पिंटू नाग पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने तथा सरकारी जमीन को पुनः मुक्त कराने की मांग की.स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता पायल राय ने कहा कि जलभराव की समस्या के कारण डेंगू सहित विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.हालांकि, पार्षद पिंटू नाग ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने फोन पर कहा कि जिस जमीन को लेकर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह जमीन उनके वार्ड के अंतर्गत ही नहीं आती. उनके अनुसार संबंधित जमीन सरकारी नहीं है और उसकी खरीद-बिक्री कई वर्ष पहले ही हो चुकी है.

उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है और उन्हें बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है.प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे श्रीरामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे और व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे.

भारी मात्रा में फेंसिडिल के साथ युवक गिरफ्तार

सूती : सूती थाने की पुलिस की सतर्कता से भारी मात्रा में फेंसिडिल बरामद किया गया है. मंगलवार देर रात सूती के सुजनीपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास विशेष नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने डेढ़ हजार बोतल फेंसिडिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया.बुधवार को पुलिस ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई. पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित कफ सिरप की इस बड़ी खेप को जब्त कर लिया है. यह जांच की जा रही है कि आरोपित युवक इतनी बड़ी मात्रा में फेंसिडिल कहां ले जा रहा था और इस तस्करी गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल है.

दुर्गापुर में पूर्व बोरो चेयरमैन रामाप्रसाद हालदार गिरफ्तार, अदालत परिसर में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन

पश्चिम बर्दवान : दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व बोरो चेयरमैन एवं पूर्व पार्षद रामाप्रसाद हालदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन पर अवैध वसूली, राजनीतिक अफवाह फैलाने, विरोधी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने तथा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.पुलिस सूत्रों के अनुसार, रामाप्रसाद हालदार के खिलाफ वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव से जुड़े कई मामलों की जांच चल रही थी. आरोप है कि चुनाव से पहले और बाद में भी उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को डराने-धमकाने, विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने तथा अवैध वसूली जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया.बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि रामाप्रसाद हालदार बर्दवान की ओर से बुदबुद इलाके में आ रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर उन्हें हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया.रामाप्रसाद हालदार दुर्गापुर नगर निगम के बोरो नंबर-2 के निवर्तमान चेयरमैन रह चुके हैं. साथ ही वे निगम के वार्ड नंबर-20 के पूर्व पार्षद भी थे. स्थानीय राजनीति में उन्हें तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता रहा है.गिरफ्तारी के बाद उन्हें दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने अदालत से जांच को आगे बढ़ाने और विभिन्न आरोपों की पड़ताल के लिए उनकी पुलिस हिरासत की मांग की है.अदालत परिसर में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक वहां पहुंच गए. प्रदर्शनकारियों ने रामाप्रसाद हालदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. 'चोर-चोर' के नारों से पूरा अदालत परिसर गूंज उठा. कई प्रदर्शनकारी उनके विरोध में जूते-चप्पल दिखाते हुए भी नजर आए.भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सत्ता में रहते हुए पूर्व तृणमूल नेता ने अपने पद का दुरुपयोग किया और आम लोगों को परेशान किया. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की.

न्यूज कॉर्नर

मौत से मचा हड़कंप

कुल्टी : कुल्टी थाना अंतर्गत बराकर फाड़ी क्षेत्र इलाके के आलू गद्दी स्थित 24 वर्षीय युवक सोनू विश्वकर्मा की रहसमय मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है,सोमवार से लापता युवक का शव बुधवार को कुल्टी थाना अंतर्गत पुनरीगराम जंगल से बरामद किया गया. सव की पहचान होते ही परिजनों में मातम पसर गया.जबकि स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह बना ग्राम जंगल के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे,तभी उन्हें तेज बदबू महसूस हुआ.लोग जब जंगल के भीतर पहुंचे, तो वहां एक सड़ी गली लाश पड़ी मिली,घटना की सूचना मिलते ही कुल्टी थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंची,और सव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू किया.प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस को संदेह हुआ कि स्व किसी लापता युवक का हो सकता है,इसके बाद बराकर फाड़ी क्षेत्र से सोनू विश्वकर्मा के परिजनों को बुलाया गया.परिजनों ने मौके पर पहुंच कर परिवार ने स्व की पहचान सोनू के रूप में की,पहचान होते ही रो रो कर परिवार का बुरा हाल होगया.पुलिस ने सव को आसनसोल जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.उसके बाद जब स्व को बराकर लाया गया,तो स्थानीय लोगों और परिजनों का गुस्सा फुट पड़ा.लोगों ने रास्ते पर सव को रखकर टायर जलाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया.प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हत्या के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी,और कड़ी सजा की मांग की है.मृतक के पिता गणेश विश्वकर्मा ने बताया कि रविवार रात सोनू घर से यह कह कर निकला कि वह परोस में रहने वाले एक मित्र के घर रुकने जा रहा है,लेकिन अगले दिन वह सुबह तक घर वापस नहीं लौटा,काफी खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चला तो कुल्टी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, सोनू का मोबाइल भी लगातार बंद रहा.जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई,अब पुलिस लगातार प्रयास कर रही की इसके पीछे किसका हाथ है,और मामल की जांच में जुट गई है.पुलिस सूत्रों के अनुसार सोनू की मौत कर्ज में डूबे हुए कारण से हुई है,सोनू उपर कर्ज इतना था कि इसने ही रचा था अपरहण साजिश,जिसके बाद इसके परिवार से 6 लाख की मांग की गई थी,उससे पहले ही साथियों के साथ पैसा बंटवारे को लेकर आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्तो ने ही ले ली सोनू की जान,फिलहाल पुलिस रोनी घोष नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है,और मामले की जांच पुलिस कर रही है,और भी जो इस मामले में शामिल है उन्हें पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी.

पंचायत प्रधान के घर घेराव, भ्रष्टाचार के आरोपों पर भड़के ग्रामीण

कूचबिहार : विधानसभा चुनाव-2026 के बाद से सरकारी सेवाओं से वंचित और प्रधान की कथित अनुपस्थिति को लेकर बुधवार को जामालदह ग्राम पंचायत क्षेत्र में भारी बवाल देखने को मिला. 164 नंबर गोपालपुर इलाके के ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान गीता बर्मन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उनके घर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया.ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के बाद से ही प्रधान क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं,

कुल्टी में परित्यक्त ईसीएल क्वार्टर से तिरपाल, कंबल और कपड़ों का जखीरा बरामद

पश्चिम बर्दवान : आसनसोल नगर निगम के वार्ड 102 अंतर्गत राधानगर के पोइडी इलाके में स्थित एक परित्यक्त ईसीएल क्वार्टर से बुधवार को तिरपाल, कंबल, साड़ियां, धोती, लुंगी, चूड़ीदार और अन्य कपड़ों की बड़ी खेप बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं.भाजपा नेता एवं बीएमएस जिलाध्यक्ष गोविंद माझी ने दावा किया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक बंद पड़े ईसीएल क्वार्टर में संदिग्ध सामान रखा गया है. सूचना पाकर भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और खिड़की से अंदर बड़े-बड़े बोरे दिखाई देने पर पुलिस तथा प्रशासन को खबर दी. सूचना पाकर नियामतपुर चौकी की पुलिस और ईसीएल अधिकारियों की मौजूदगी में क्वार्टर का ताला

तोड़कर तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान भारी मात्रा में कंबल, तिरपाल, बच्चों के कपड़े, महिलाओं की साड़ियां तथा पुरुषों की धोती-लुंगी बरामद हुई.भाजपा का आरोप है कि ये सामान गरीब लोगों में वितरण के लिए थे, लेकिन उन्हें लंबे समय से छिपाकर रखा गया था. गोविंद माझी ने आरोप लगाया कि जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई और इन्हें कहीं और भेजने की तैयारी की जा रही थी. उन्होंने मामले में स्थानीय तृणमूल पार्षद की भूमिका की जांच की मांग की.वहीं, ईसीएल के सोदपुर एरिया के अधिकारी एस अहमद ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि पांच पैकेट कंबल, तिरपाल, साड़ियां, लुंगी, धोती, चूड़ीदार सहित अन्य सामान बरामद हुआ है. सभी वस्तुओं को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पुलिस को सौंप दिया गया है. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सामान सरकारी था या निजी तथा उसका वास्तविक मालिक कौन है.दूसरी ओर वार्ड 102 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद सौरभ माझी ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जिस परित्यक्त ईसीएल क्वार्टर से सामान मिला, वह उनकी निजी संपत्ति नहीं है. वहां सामान कैसे पहुंचा, किसने रखा और क्वार्टर किसके नाम आवंटित था, इसकी जांच ईसीएल और प्रशासन को करनी चाहिए.उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

आसनसोल में 80 अन्नपूर्णा भंडार के लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित

पश्चिम बर्दवान: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' का बुधवार को औपचारिक शुभारंभ किया गया. पश्चिम बर्दवान जिला प्रशासन की ओर से कल्याणपुर हाउसिंग स्थित जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में योजना के 80 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए.

मिली जानकारी के अनुसार, आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आसनसोल उत्तर, आसनसोल दक्षिण और कुल्टी विधानसभा क्षेत्रों के कुल 80 लाभुकों को कार्यक्रम में स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए, जबकि दुर्गापुर नगर निगम क्षेत्र के लाभुकों को दुर्गापुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वीकृति पत्र दिए गए.

इस अवसर पर आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का संकल्प राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिया था और आज उसी संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है.उन्होंने

कहा कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी.उन्होंने बताया कि गत एक जून से सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई थी और अन्नपूर्णा भंडार योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम है.कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी एस. पोन्नमबलम ने बताया कि आसनसोल नगर निगम और दुर्गापुर नगर निगम क्षेत्र में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है. 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं के आवेदन की जांच के बाद उन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं.उन्होंने बताया कि अन्नपूर्णा भंडार योजना के आवेदन पत्र सभी नगर निगम कार्यालयों, बीडीओ कार्यालयों तथा ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं.

जिला प्रशासन के अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर आवेदनों की जांच कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके.कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा योजना का शुभारंभ किए जाने के बाद आसनसोल और दुर्गापुर में भी लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए.

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए बंगाल सरकार ने बीएसएफ को सौंपी 31.9 एकड़ जमीन

पश्चिम बंगाल में 20 जून को मनाया जाएगा 'राज्य दिवस', कैबिनेट ने दी मंजूरी

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 20 जून को आधिकारिक रूप से 'पश्चिम बंगाल राज्य दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने बताया कि 20 जून, 1947 को तत्कालीन बंगाल विधानसभा में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था. इस प्रस्ताव ने बंगाल के विभाजन और पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था. इसी ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 20 जून को 'पश्चिम बंगाल दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है. दिलीप घोष ने कहा कि अब से हर वर्ष 20 जून को राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इससे पहले भाजपा 20 जून को 'पश्चिम बंगाल दिवस' के रूप में मनाती रही है, जबकि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार बंगाली नववर्ष 'पोइला बोइशाख' के दिन, यानी 14 या 15 अप्रैल को राज्य दिवस मनाती थी. मंत्री ने यह भी घोषणा की कि जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूरे राज्य में वर्षभर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जाएगी. डॉ. मुखर्जी की जयंती 6 जुलाई को मनाई जाती है. उन्होंने बताया कि वर्षभर चलने वाले कार्यक्रमों के संचालन के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें मंत्री, विधायक और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा 6 जुलाई को एक विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें चयनित स्थान पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी.

कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी कार्य को तेज करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 31.905 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी है. यह प्रक्रिया कई वर्षों से लंबित थी. राज्य के पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी. दिलीप घोष ने बताया कि सरकार ने बीएसएफ को सीमा पर बाड़बंदी और स्थायी सीमा चौकियों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि सरकार के पहले मंत्रिमंडल निर्णय के अनुरूप बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के नौ स्थानों पर कुल 31.905 एकड़ भूमि सीमा सुरक्षा बल को सौंपी गई है. मंत्री के अनुसार, भूमि एवं भूमि सुधार विभाग ने मालदा, मुर्शिदाबाद और कूचबिहार जिलों में तीन स्थानों पर स्थायी सीमा चौकियां स्थापित करने के लिए 1.53 एकड़ भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर जिले में सीमा पर बाड़बंदी कार्य को सुगम बनाने के लिए 11 स्थानों पर 12.72 एकड़ भूमि सीमा सुरक्षा बल को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है. भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए भूमि हस्तांतरण का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है. इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई. दिलीप घोष ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा क्षेत्र में स्थित 20 एकड़ सरकारी भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया. बाद में यह भूमि सेवक-रंगपो रेल परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी. राज्य सरकार का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में बाड़बंदी और स्थायी चौकियों के निर्माण से सीमा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तथा अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी.

भाजपा सरकार ने 'मां कैंटीन' का नाम बदलकर किया 'मां आहार', योजना जारी रखने का किया ऐलान

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजना 'मां कैंटीन' को जारी रखने का फैसला किया है. हालांकि, योजना का नाम बदलकर अब 'मां आहार' कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने राज्यभर में इस योजना के विस्तार की भी घोषणा की है. बुधवार को नवान्न में नई सरकार की पूर्ण मंत्रिपरिषद की पहली बैठक के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'मां कैंटीन' योजना का नाम बदलकर 'मां आहार' रखा गया है और इसे पहले की तरह जारी रखा जाएगा. दिलीप घोष ने कहा कि अभी तक राज्य में 390 केंद्रों से इस योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाता था. अब 110 नए 'मां आहार' केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इसके बाद राज्य में कुल 500 केंद्रों से लोगों को मात्र पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन मिलता रहे. इसी उद्देश्य से योजना को बंद करने के बजाय उसका विस्तार करने का निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि 'मां कैंटीन' योजना की शुरुआत 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर की गई थी. सबसे पहले दक्षिण कोलकाता के देशप्रिय पार्क क्षेत्र में श्रमिकों के लिए 5 रुपये में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया था.

अभिषेक का पार्टी से कोई संबंध नहीं, ममता बनर्जी सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन दें : ऋतब्रत बनर्जी

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी संघर्ष के बीच नवमान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता ऋतब्रत बंद्योपाध्याय ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, जबकि ममता बनर्जी को वह एक वरिष्ठ नेता के रूप में पार्टी की मुख्य सलाहकार की भूमिका में देखना चाहते हैं. बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ऋतब्रत ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की कोई भूमिका नहीं रहेगी. उनके साथ हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं है. जनता के साथ भी उनका कोई जुड़ाव नहीं है. यदि ऐसा होता तो चुनावी हार के बाद वह 26 दिनों तक सार्वजनिक रूप से गायब नहीं रहते, बल्कि लोगों के बीच आते. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद हुई घटनाओं के दौरान अभिषेक बनर्जी जनता के समर्थन का दावा करते रहे, लेकिन बाद में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखना पड़ा. ऋतब्रत ने कहा कि उनका समूह अभिषेक बनर्जी को लेकर किसी प्रकार की चर्चा करना नहीं चाहता और पार्टी की राजनीति को उनके प्रभाव से अलग रखना चाहता है. इसके विपरीत, ऋतब्रत ने तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि वह राज्य और देश की एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं. उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि ममता बनर्जी का लंबा राजनीतिक अनुभव है. हमारी इच्छा है कि वह पार्टी की मुख्य सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन देती रहें और संगठन को दिशा प्रदान करें. ऋतब्रत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर खुला संघर्ष सामने आ चुका है. हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को विपक्ष का नेता मान्यता दिए जाने के बाद पार्टी के भीतर दो स्पष्ट धड़े दिखाई दे रहे हैं. दरअसल, ऋतब्रत का यह बयान तृणमूल कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की भूमिकाओं को अलग-अलग परिभाषित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. एक ओर उन्होंने ममता बनर्जी को पार्टी के लिए स्वीकार्य और सम्मानित नेतृत्व बताया, वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी से पूरी तरह दूरी बनाने का संकेत दिया.

बनगांव में तृणमूल पार्षद पापाई राहा गिरफ्तार

कोलकाताः उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव नगर पालिका के वार्ड संख्या 14 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद पापाई राहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन पर कथित तौर पर वसूली, धमकी देने और विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं. इस कार्रवाई के बाद इलाके में व्यापक चर्चा और राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पापाई राहा के खिलाफ लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा कई शिकायतें दर्ज कराई जा रही थीं. आरोप है कि उनके खिलाफ इलाके में दबंगई, अवैध वसूली और लोगों को धमकाने संबंधी शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं. इन शिकायतों के आधार पर बुधवार दोपहर बनगांव थाना पुलिस ने गोपालनगर क्षेत्र में अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. खबर लिखे जाने तक पार्टी की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी. वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपित के खिलाफ दर्ज शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना को लेकर बनगांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच व्यापक चर्चा का माहौल बना हुआ है.

खेल वही है, सिर्फ अंपायर बदल गया है : अधीर चौधरी

कोलकाताः एक दौर में कांग्रेस को तोड़कर तृणमूल का गठन करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में मची टूट पर पूर्व कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तीखा तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि अब वही खेल हो रहा है. इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है. उन्होंने कहा कि जिस दल-बदल और राजनीतिक खेल की शुरुआत कभी ममता बनर्जी ने की थी, आज वही खेल उनके खिलाफ खेला जा रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि अब अंपायर और रेफरी बदल गए हैं. बहरमपुर में आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल में जारी टूट को लेकर कहा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2016 में विधानसभा के भीतर कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाने से रोकने का प्रयास किया गया था और उस समय ममता बनर्जी स्वयं इस राजनीतिक खेल की निर्णायक थीं. पूर्व सांसद ने कहा कि जिस दल-बदल के खेल की शुरुआत एक दिन आपने की थी और कहा था कि खेला होगा, उसी खेल में उस समय आप अंपायर और रेफरी थीं. आज भी वही खिलाड़ी मैदान में हैं, केवल अंपायर और रेफरी बदल गए हैं. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब तृणमूल से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को 58 विधायकों के समर्थन के आधार पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता मिल चुकी है. विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद विपक्ष के नेता का कक्ष भी ऋतब्रत को सौंप दिया गया है. तृणमूल के बागी विधायकों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच संभावित राजनीतिक समीकरणों पर भी अधीर रंजन चौधरी ने टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि भाजपा और बागी विधायक दोनों ही फिलहाल एक-दूसरे से प्रत्यक्ष दूरी बनाए हुए हैं. अधीर ने कोविड काल के लोकप्रिय नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि दो गज की दूरी बहुत जरूरी है. उनके अनुसार भाजपा जानती है कि यदि इन विधायकों को सीधे पार्टी में शामिल किया गया तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है, जबकि बागी विधायक भी अपने मतदाताओं की प्रतिक्रिया को लेकर सतर्क हैं. उन्होंने दावा किया कि तृणमूल के कई विधायक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आए हैं और सीधे भाजपा में शामिल होने पर उन्हें जनाक्रोश का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वे अंततः भाजपा के राजनीतिक प्रभाव में काम करने को मजबूर हो सकते हैं. अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के केवल एक महीने के भीतर तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिखाई दे रही है. उन्होंने दावा किया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों के इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है और कई स्थानीय निकायों में भी तृणमूल की पकड़ कमजोर पड़ रही है. कांग्रेस नेता ने तृणमूल कांग्रेस के गठन के इतिहास का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी स्वयं कांग्रेस छोड़कर बाहर आई थीं और वर्ष 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था. उनके अनुसार उस समय कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद पैदा हुए थे, जिसके बाद ममता ने अलग राजनीतिक राह चुनी थी.

हस्ताक्षर जालसाजी मामला: हाई कोर्ट ने अभिषेक को जबरदस्ती कार्रवाई से सुरक्षा के लिए याचिका दायर करने की दी अनुमति

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनके वकील शीर्षान्या बनर्जी ने जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे का ध्यान इस ओर दिलाया और केस दायर करने की अनुमति मांगी. याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाई कोर्ट से उस नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया है. जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे ने केस दायर करने की अनुमति दे दी है. इस मामले की सुनवाई 5 जून को गर्मी की छुट्टी बेंच द्वारा किए जाने की उम्मीद है. यह मामला मुख्य रूप से विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी कांड से जुड़ा है. इसी सिलसिले में, सीआईडी अधिकारी पिछले शनिवार 30 मई दोपहर में अभिषेक के कालीघाट रोड स्थित घर पर गए थे. उन्हें वहीं नोटिस दिया गया, जिसे अभिषेक ने खुद हस्ताक्षर करके लिया. नोटिस में अभिषेक को पूछताछ के लिए सोमवार 1 जून को भबानी भवन में सीआईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था. उन्हें उस दिन दोपहर 12 बजे वहां पेश होने का निर्देश दिया गया था. हालांकि, सोमवार सुबह अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी को एक पत्र भेजा जिसमें बताया गया कि हाल ही में सोनारपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान उन पर हमला हुआ था. इसलिए, वह बीमार पड़ गए थे और अभी अपने डॉक्टरों की सलाह पर आराम कर रहे थे. इसलिए, उन्होंने कहा कि उनके लिए उस समय जांच करने वालों के सामने पेश होना मुमकिन नहीं है. पत्र में, उन्होंने सीआईडी से 15 दिन का समय मांगा. लेकिन, सीआईडी इसका समय बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी. दूसरी बार, सोमवार शाम को, सीआईडी के अधिकारी डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर गए. मांगे गए 15 दिनों के बजाय, उन्होंने अभिषेक को पेश होने के लिए सात दिन दिए. उन्हें एक नया नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें 8 जून को जांचकर्ता के सामने खुद पेश होने का निर्देश दिया गया. अभिषेक बनर्जी ने अब कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें सीआईडी द्वारा जारी इस नए समन नोटिस को कैंसल करने की मांग की गई है. खास बात यह है कि हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच के लिए सीआईडी ने पहले ही एक एसआईटी बना दी है. इस टीम को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) रैंक का एक अधिकारी लीड कर रहा है, साथ में दो सब-इंस्पेक्टर भी हैं. जांच करने वालों का दावा है कि विधानसभा के डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर को लेकर कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, और जांच इसी आधार पर आगे बढ़ रही है.

अन्नपूर्णा भंडार योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम : अग्निमित्रा पाल

कोलकाताः राज्य की महिला एवं शिशु कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि अन्नपूर्णा भंडार योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है. बुधवार को उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद जिस प्रकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का संकल्प लिया गया था, उसे अब धरातल पर उतारा जा रहा है. पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि उनके लिए यह गर्व और सम्मान का विषय है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत लाखों महिलाओं के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि भेजी गई है. उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक मजबूत और स्वस्थ विपक्ष की पक्षधर रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सरकार चाहती है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए. यदि सरकार अच्छा कार्य करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए और यदि कोई गलती होती है तो उसकी आलोचना भी की जानी चाहिए. लेकिन हर मुद्दे पर केवल विरोध करने से विपक्ष की विश्वसनीयता कमजोर होती है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को आंदोलन करने और अपनी बात रखने का अधिकार है. कानून के दायरे में रहकर अनुमति लेकर कहीं भी आंदोलन किया जा सकता है, बशर्ते आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो. अग्निमित्रा पाल ने कहा कि देश की जनता अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जागरूक और संवेदनशील हो चुकी है. उन्होंने कहा कि लोग आर्थिक रूप से भले ही साधारण हों, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद सजग हैं और डर, धमकी या दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करते.

बंगाल सरकार ने सौरव गांगुली की सुरक्षा में किया बदलाव

जेड की जगह वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (कैब) के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती करने का फैसला किया है. अब तक सौरव को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन अब उन्हें 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी. इस फैसले के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था दो स्तर नीचे आ जाएगी. इस संबंध में सौरव गांगुली से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से विभिन्न राजनीतिक नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों को दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पदभार संभालने के बाद नवान्न में आयोजित एक बैठक में स्पष्ट किया था कि जिन लोगों को वास्तविक सुरक्षा खतरा नहीं है, उन्हें अनावश्यक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इसके बाद राज्य पुलिस ने राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ उन अन्य लोगों की सुरक्षा की भी समीक्षा शुरू की, जिन्हें राज्य सरकार की ओर से विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती थी. सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की अतिरिक्त सुरक्षा वापस ली गई थी. सरकार ने स्पष्ट किया था कि उन्हें सांसद के रूप में निर्धारित सुरक्षा ही मिलेगी. इसके बाद कई तृणमूल नेताओं और पूर्व पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था में भी कटौती की गई. अब इस सूची में सौरव गांगुली का नाम भी शामिल हो गया है. राज्य सरकार के इस फैसले को सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है.

बिहार के मंत्री जमां खान ने एयरपोर्ट पर किया हज यात्रियों का स्वागत

कोलकाताः कोलकाता पहुंचे बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता जमां खान ने कोलकाता एयरपोर्ट पर हज यात्रियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें फूल माला के साथ उनका स्वागत किया. मंत्री जमां खान ने हज की पवित्र यात्रा पूर्ण कर स्वदेश लौट रहे हाजियों के स्वागत कर उनका हालचाल पूछा. इस दौरान सामाजिक कर्मी हाजी मतलूब खान ने उक्त जानकारी देते हुए आज मीडिया कर्मियों को बताया कि बिहार के मंत्री जमां खान इससे पहले बंगाल आकर पहले भी हाजियों को हज यात्रा पर जाने से पहले उन्हें विदा कर चुके हैं. मंत्री जमां खान ने एयरपोर्ट पर एनडीए कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत एवं सम्मान के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया.

पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की हेल्प लाइन, शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल

कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को जनहित में हेल्प लाइन और ईमेल आईडी जारी किया है. इसके विभिन्न सरकारी सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए या राज्य सरकार से सीधे शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्प लाइन और ईमेल आईडी जारी किया गया है. हेल्प लाइन नंबर है 82820 8282 एवं ईमेल आईडी - asapwb.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है. मिली जानकारी के अनुसार, यह सेवा सोमवार से शनिवार तक हर सप्ताह सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक चालू रहेगी.

मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

15 महिलाओं से शादी करने का आरोप

कोलकाताः कोलकाता पुलिस ने एक युवक को मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए महिलाओं से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर पैसे और गहने ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित ने इसी तरह कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया और कथित तौर पर 15 महिलाओं से शादी की. पुलिस के द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित की पहचान मध्य कोलकाता के बउबाजार निवासी मतीउर रहमान के रूप में हुई है. वह मैट्रिमोनियल साइटों पर खुद को माणिक रॉय नाम से पंजीकृत करता था. इसी नाम से उसकी पहचान उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी की एक युवती से हुई थी. आरोप है कि मतीउर ने खुद को एक उच्च वेतन वाली नौकरी में कार्यरत बताते हुए दावा किया था कि उसकी वार्षिक आय 1.5 करोड़ रुपये है. शादी के सपने दिखाकर उसने युवती और उसके परिवार का विश्वास जीत लिया. कुछ समय बाद उसने विभिन्न बहानों से युवती पर पैसे और सोने के आभूषण देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. शिकायतकर्ता युवती का आरोप है कि उसने आरोपित को 85 हजार रुपये नकद, एक सोने का ब्रेसलेट और अन्य कीमती सामान दिया. शुरुआत में उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ. बाद में आरोपित ने अपने एक रिश्तेदार की मृत्यु का बहाना बनाकर फिर से पैसों की मांग की. उसने युवती को एक बैंक खाते में पैसे भेजने के लिए कहा और बताया कि उसका रिश्तेदार मुंबई में रहता था. इसी दौरान युवती को कुछ ऐसी जानकारी मिली, जिससे उसे संदेह हुआ कि आरोपित का वास्तविक घर पूर्व बर्दवान जिले में है. संदेह गहराने पर युवती ने आरोपित के सोशल मीडिया खातों की जांच की, जहां उसे कई अन्य महिलाओं के बारे में जानकारी मिली. जब उसने उनसे संपर्क किया, तो कथित तौर पर पता चला कि आरोपित सभी महिलाओं से एक जैसी बातें करता था और उनसे पैसे ऐंठता था. कुछ महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपित ने उनसे शादी की थी. इसके बाद युवती ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंगलवार रात आरोपित को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित ने कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया तथा धोखाधड़ी का नेटवर्क कितना बड़ा है.

दक्षिण 24 परगना के कुलतली में हिरासत में लिये गये 18 बांग्लादेशी

कोलकाताः दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली थाना क्षेत्र के गोदाबर इलाके से कुलतली थाना पुलिस ने 18 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. इस समूह में 12 वयस्क पुरुष एवं महिलाएं तथा छह बच्चे शामिल हैं. इनमें से किसी के पास भी वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं. गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए एक विशेष अभियान में बुधवार तड़के कुलतली के गोदाबर क्षेत्र स्थित एक स्थानीय ईंट-भट्टे से कुल 18 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया. पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में 12 वयस्क पुरुष एवं महिलाएं हैं, जबकि शेष 6 बच्चे हैं. बिना किसी वैध दस्तावेज के अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर वे पिछले कई वर्षों से भारत में रह रहे थे.

आपकी वेदना, हमारी संवेदना

युवा शक्ति समाचार पत्र उठावना का विज्ञापन मात्र 1500 रुपये में प्रकाशित करता है

(साइज 12x8)

सम्पर्क :

मो. : 9831572125, 9831494084

www.yuvashakti.news.com

email: yuvashakti@hotmail.com

संपादकीय

कामयाब होने के लिए स्वयं पर भरोसा होना चाहिए

कोलकाता | गुरुवार | 4 जून, 2026

नशे पर शिकंजा

निस्संदेह, नशे का निरंतर फैलता काला कारोबार एक राष्ट्रीय संकट है. देश के विभिन्न भागों में करोड़ों-अरबों रुपये मूल्य के विदेशों से आने वाले नशीले पदार्थों की बरामदगी भयावह संकट की तसवीर उकेरती है. संगठित विदेशी अपराधियों की साजिशों और देश में फैले नशा तस्करों का गठजोड़, इस नशीले जहर के कारोबार को चला रहा है. आज जरूरत इस बात की है कि देश की तमाम खुफिया एजेंसियां व राज्य के विशेष पुलिस बल योजनाबद्ध ढंग से नशा कारोबारियों की कमर तोड़ें. लेकिन फिर भी कई राज्यों द्वारा चलाये जा रहे नशा विरोधी अभियान बिगड़ते हालात सुधारने में किसी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं. पिछले दिनों पंजाब में भी ऐसा अभियान चलाया गया. अब सीमावर्ती जम्मू-कश्मीर में वर्षों से गहराते नशे के संकट के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है. सवाल यह है कि राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने में इतना वक्त क्यों लगा? अब भले ही देर से ही सही, यह पहल शुरू करना वक्त की जरूरत है. नशे के नश्तर से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और कई घरों के चिराग असमय बुझ रहे हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीस जिलों का दौरा करके सौ दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं. वहीं इस अभियान का सुखद पहलू यह है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में, इस कोशिश को प्रतिबंधित संगठन जमाते-ए-इस्लामी के एक गुट का भी समर्थन मिला है. कहना कठिन है कि इस समर्थन का हकीकत में असर कितना होगा. लेकिन इस घोषणा ने सकारात्मक संदेश जरूर दिया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही इस भयावह होते संकट का मुकाबला किया जा सकता है. सही मायने में समाज में व्याप्त तमाम वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए, सामूहिक व निरंतर प्रयासों से ही नशा मुक्ति की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है. वास्तव में नशा विरोधी अभियान के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली जटिलताओं के मुकाबले के लिये कुछ दिन, कुछ माह के अभियान के बजाय साल में 365 दिन चलने वाली रणनीति अपनाने की जरूरत है. कभी-कभार चलाए जाने वाले अभियान इसके लक्ष्य को पाने में ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकते. इस संकट के समाधान के लिये नशे की लत के सामाजिक पहलुओं की भी व्यापक पड़ताल जरूरी है. कारगर समाधान हेतु सामाजिक स्तर पर रणनीति बनाने की जरूरत होती है. निस्संदेह, नशे की लत के तमाम कारण हमारे समाज में विद्यमान हैं. जिनके निराकरण की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है. मसलन इस व्यसन के मूल में समाज में व्याप्त बेरोजगारी, निराशा, सामाजिक व आर्थिक असमानताएं, बुरी संगत का असर तथा मादक पदार्थों की समाज में आसान उपलब्धता आदि कारक निहित हैं. चिंताजनक है कि नशा अब स्कूल-कालेजों तक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है. कई राज्यों में नशे की आपूर्ति में बच्चों को इस्तेमाल करने के चिंताजनक उदाहरण सामने आए हैं. वहीं यदि नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों में शिथिलता अपनायी जाती है तो सख्ती से हासिल होने वाली उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं. यह सत्य है कि नशा एक ऐसा रोग है, जिसका कोई आसान इलाज उपलब्ध नहीं है. जहां एक ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है, तो दूसरी ओर इसकी तलब को काबू करने के लिये भी प्रयास जरूरी हैं. दुर्भाग्यपूर्ण है कि नशे की डोज जुटाने के लिये कुछ छात्र व युवा अपराध की राहों में फिसल जाते हैं. इसलिये जरूरी हो जाता है कि नियमित रूप से नशा तस्करों और ड्रग पेडलरों की गिरफ्तारी करके तुरंत सजा दी जाए. वहीं दूसरी ओर नशे की खरीद-फरोख्त में संलिप्तता पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने, पासपोर्ट निरस्त करने से भी जहरीले कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है. साथ ही सीमावर्ती संवेदनशील राज्यों में, जहां सीमा पार से नशे की तस्करी आतंकवाद को जिंदा रखने के लिये की जा रही है, वहां अतिरिक्त सावधानी की भी जरूरत है. नशा तस्करों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सजा देना, इस अभियान में मददगार साबित होगा.

दुनिया की आधी आबादी जल संकट का शिकार

– क्रांति कुमार पाठक

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में आधी आबादी यानी करीब 4 अरब लोग साल में कम से कम एक महीने गंभीर जल संकट का सामना करती है. रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे बड़े शहरों में आधे शहरों को गंभीर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है. इनमें दिल्ली, बीजिंग, न्यूयॉर्क और रियो जैसे बड़े शहर शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, नदियां और झीलें सिकुड़ रही हैं, भूमिगत जल स्तर गिर रहा है और वाटरलैंड्स सूख रही हैं. जमीन धंस रही है सिंकहोल बन रहे हैं और रेगिस्तान फैल रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले कई दशकों के दौरान जलवायु परिवर्तन, सिमटते भूजल स्रोतों, अत्यधिक जल दोहन, बढ़ते प्रदूषण और कुप्रबंधन के कारण कई क्षेत्र 'वैश्विक जल दिवालियापन' के युग में प्रवेश कर चुके हैं. दरअसल, गर्मी और पानी का चोली दामन का साथ है. भारत की बात करें, तो इस समय गर्मी अपने चरम पर है और देशभर में पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है. भारत में, लगभग 60 करोड़ लोग (देश की आधी आबादी) उच्च से चरम जल तनाव के बीच जी रहे हैं. भारत वैश्विक भूजल का लगभग 25 फीसदी अकेले इस्तेमाल करता है, जिससे कई क्षेत्रों में वाटर लेवल खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है. देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न प्रदेशों से मिल रही खबरें बेहद चिंताजनक है. अनेक स्थानों पर पानी की किल्लत से परेशान लोग आंदोलन कर रहे है. केंद्रीय जल आयोग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय कुल 63.232 अरब घन मीटर पानी उपलब्ध है, जो सामान्य भंडारण से लगभग 24 फीसदी अधिक है, लेकिन 30 अप्रैल 2026 तक देश के 166 जलाशयों में कुल 71.082 अरब घन मीटर (बीसीएम) पानी बचा था, जो उनकी कुल क्षमता का 38.72 फीसदी था. अब 14 मई की रिपोर्ट में यह घटकर 63.232 बीसीएम रह गया है, यानी केवल 34.45 फीसदी. महज दो हफ्तों में करीब 8 बीसीएम पानी कम हो गया. केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि मौजूदा जल भंडारण पिछले वर्ष और 10 साल के औसत से अभी भी बेहतर है, लेकिन लगातार गिरता स्तर यह संकेत दे रहा है कि गर्मी बढ़ने और मानसून आने में देरी होने पर कई राज्यों में पेयजल, सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन पर गंभीर दबाव पड़ सकता है. जून के अंत तक हालात और कठिन हो सकते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां जलाशय पहले ही आधे से नीचे पहुंच चुके हैं. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है. कई राज्य ऐसे हैं जो भूजल की कमी के चरम बिंदु को पार कर चुके हैं. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 2026 तक गंभीर रूप से भूजल संकट गहरा सकता है. जल के बिना मानव जिन्दा नहीं रह सकता. क्योंकि मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल होता है. यह सब मानव को मालूम होते हुए भी जल को बिना सोचे-विचारे हमारे जल-स्रोतों में ऐसे प्रदूषित मिला रहा है जिससे मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है. जल हमें नदी, तालाब, कुएँ, झील आदि से प्राप्त हो रहा है. जल की उपलब्धता को लेकर वर्तमान में भारत ही नहीं अपितु समूचा विश्व चिन्तित है. जल ही जीवन है. जल के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती. मानव का अस्तित्व जल पर निर्भर करता है. जनसंख्या में तेजी हो रही वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगीकरण, जलवायु परिवर्तन और अकुशल जल प्रबंधन प्रथाओं जैसे कारकों के संयोजन की वजह से पानी की कमी की व्यापक समस्या पैदा होती जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में पानी की कमी के गंभीर और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. भूजल की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये भूजल का स्तर और न गिरे इस दिशा में काम किए जाने के अलावा उचित उपायों से भूजल संवर्धन की व्यवस्था हमें करनी होगी. पानी की कमी के चलते निरन्तर खोदे जा रहे गहरे कुओं और ट्यूबवेलों द्वारा भूमिगत जल का अन्धाधुन्ध दोहन होने से भूजल का स्तर निरन्तर घटता जा रहा है. देश में जल संकट का एक बड़ा कारण यह है कि जैसे-जैसे सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़ता गया वैसे-वैसे भूगर्भ के जल के स्तर में गिरावट आई है. भूजल दोहन के अंधाधुंध दुरुपयोग को यदि समय रहते रोका नहीं गया, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे. सरकार को जनता में जागरूकता लाने के लिए विशेष प्रबन्ध और उपाय करने होंगे. आवश्यकता इस बात की है कि हम जल के महत्व को समझे और एक-एक बूंद पानी का संरक्षण करें तभी लोगों की प्यास बुझाई जा सकेगी. *(उपसंपादक दैनिक एक संदेश)*

न्यायालय के आलोक में बेटी का अधिकार

–डॉ. निवेदिता शर्मा

भारतीय न्यायपालिका ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि न्याय हमेशा समाज की बदलती वास्तविकताओं को स्वीकार करते हुए समानता, गरिमा और मानवीय अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम है. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया हालिया निर्णय, जिसमें विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति एवं आश्रित कोटे के लाभों से बाहर रखने को असंवैधानिक ठहराया गया है, भारतीय न्यायिक इतिहास में महिला अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय कहलाएगा. वास्तव में यह निर्णय उस सोच को भी चुनौती देता है जो विवाह के बाद बेटी को उसके माता-पिता के परिवार से अलग मान लेने की प्रवृत्ति रखती है. कई बार माता-पिता के लिए भी और कई बार परिवार के भाई एवं अन्य कुटुम्बजनों के लिए. न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट कहा कि विवाहित पुत्री को परिवार की परिभाषा से बाहर रखना मनमाना, अनुचित तथा संविधान के समानता सिद्धांत के विपरीत है. आज न्यायालय की इस संबंध में अत्यंत सारगर्भित टिप्पणी बता रही है कि विवाह न तो बेटी और उसके माता-पिता के बीच के संबंध को समाप्त करता है और न ही यह मान लेने का कोई आधार देता है कि वह अब अपने परिवार पर आश्रित नहीं रही. इसके साथ ही यह कथन भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त भी करता है, जहां आज असंख्य विवाहित बेटियां अपने माता-पिता की देखभाल करती हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक संबल का आधार बनती हैं तथा कठिन परिस्थितियों में परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती हैं. आप यह भी कह सकते हैं कि कुलसुम निशा के मामले में न्यायालय ने कानून की व्याख्या नवीन अर्थों के साथ की है, जिसमें जीवन की वास्तविकताओं को महत्व दिया गया. याचिकाकर्ता अपनी माता के निधन के पश्चात अपनी बहनों, जिनमें एक दृष्टिबाधित बहन भी शामिल है, के भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभा रही है. वे अपनी माता के साथ रहती थीं और उचित मूल्य की दुकान के संचालन में सहयोग करती थीं. इसके बावजूद, इसलिए उनकी अर्जी अस्वीकार कर दी गई थी क्योंकि वे विवाहित थीं. अब न्यायालय ने इस आधार को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है. यह निर्णय बताता है कि न्यायपालिका व्यक्ति की वास्तविक परिस्थितियों को प्राथमिकता देती है, न कि रूढ़िगत धारणाओं को. वास्तव में यह निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना का विस्तार है. संविधान के अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है. यदि विवाहित पुत्र को परिवार का सदस्य माना जा सकता है तो विवाह के कारण विवाहित पुत्री को उस अधिकार से वंचित करना स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव ही है. उच्चतम न्यायालय ने इसी असमानता को समाप्त करते हुए एक बार फिर यह संदेश दिया है कि अधिकार व्यक्ति की योग्यता, आवश्यकता और वास्तविक

स्थिति के आधार पर निर्धारित होंगे, न कि उसके लिंग या वैवाहिक स्थिति के आधार पर. अब यदि हम भारतीय संदर्भ में इस निर्णय को देखें तो ध्यान में आता है कि यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है. भारतीय न्यायपालिका का अतीत महिलाओं और बेटियों के अधिकारों को निरंतर सुदृढ़ करने वाले निर्णयों से भरा हुआ है. वर्ष 2020 में उच्चतम न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि पुत्री जन्म से ही पैतृक संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार रखती है. इस निर्णय ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की प्रगतिशील व्याख्या की. साथ में यह भी स्थापित किया कि बेटी परिवार की समान उत्तराधिकारी है, कोई गौण सदस्य नहीं. इससे पूर्व भी विभिन्न मामलों में न्यायालय ने महिलाओं के संपत्ति अधिकार, गरिमामय जीवन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और समान अवसरों को संविधान की मूल भावना के अनुरूप सुदृढ़ किया है. हम यहां यदि भारतीय न्याय परंपरा के व्यापक इतिहास को देखें तो यह कहना अनुचित होगा कि यहां स्त्री या पुत्री के प्रति न्याय का अभाव रहा है. भारतीय संस्कृति और न्याय-दर्शन में नारी को सम्मान का केंद्र माना गया है. मनुस्मृति का प्रसिद्ध वचन भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इसका आशय यह है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, वहीं समृद्धि, सद्भाव और श्रेष्ठता का वास होता है. यद्यपि समय के साथ सामाजिक व्यवहार में अनेक विकृतियां आईं और कुछ परंपराओं का दुरुपयोग भी हुआ, किंतु भारतीय न्याय-दर्शन का मूल स्वर सदैव नारी सम्मान और संरक्षण के पक्ष में रहा है. याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति तथा अन्य प्राचीन विधि-ग्रंथों में स्त्रीधन और महिलाओं के अधिकारों को मान्यता दी गई है. भारतीय सभ्यता में माता को सर्वोच्च सम्मान दिया गया, कन्या को पूजनीय माना गया और परिवार व्यवस्था में महिला की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया गया. आधुनिक भारत का संविधान इसी सांस्कृतिक आधार को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाता है, इसलिए जब उच्चतम न्यायालय बेटियों के अधिकारों की रक्षा करता है, तब वह सिर्फ आधुनिक संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करता बल्कि भारतीय न्याय परंपरा के उस श्रेष्ठ पक्ष को भी आगे बढ़ाता है जिसमें व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि मानी गई है. उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि परिवार का अर्थ रक्त संबंधों की औपचारिक परिभाषा से ऊपर उठकर जिम्मेदारी, स्नेह, सहयोग और पारस्परिक निर्भरता है. आज की सामाजिक परिस्थितियों में यह मान लेना कि विवाह के बाद बेटी का अपने माता-पिता से संबंध समाप्त हो जाता है, वास्तविकता से परे है. अनेक परिवारों में बेटियां ही माता-पिता की सबसे बड़ी शक्ति और सहारा होती हैं इसलिए किसी कल्याणकारी योजना, अनुकंपा नियुक्ति या आश्रित कोटे के लाभ से उन्हें वैवाहिक स्थिति के आधार पर वंचित करना न्याय और समानता दोनों के विरुद्ध है. यह निर्णय उन लाखों बेटियों के लिए आशा का संदेश है जो अपने परिवारों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं. साथ ही यह प्रशासनिक तंत्र के लिए भी स्पष्ट निर्देश है कि कल्याणकारी योजनाओं का संचालन संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप किया जाए, न कि पुरानी और अप्रासंगिक धारणाओं के आधार पर. वहीं आज भारतीय न्यायपालिका का यह निर्णय इसलिए विशेष प्रशंसा का पात्र है क्योंकि उसने एक व्यापक सामाजिक संदेश दिया है कि बेटी विवाह के बाद भी बेटी ही रहती है; उसका अपने परिवार पर अधिकार, दायित्व और संबंध किसी वैवाहिक बंधन से समाप्त नहीं होते. निःस्संदेह, उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता, प्रगतिशीलता और न्यायप्रियता का उत्कृष्ट उदाहरण है. यह निर्णय आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में स्मरण किया जाएगा तथा यह संदेश देता रहेगा कि भारत की न्याय व्यवस्था में बेटी कभी पराई नहीं होती, वह सदैव ही अधिकारों और सम्मान की समान भागीदार होती है.

(लेखिका, मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं)

आपका जन्मदिन मंगलमय हो

4 जून

आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ. आपका जन्मतिथि 4 जून है. अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्मतिथि का स्वामी ग्रह राहु है. इस माह का अधिपति ग्रह बुध है. आप आजीवन बुध एवं राहु ग्रह से प्रभावी रहेंगे. आपके जीवन का प्रमुख अंग होगा व्यवधान. आपका जीवन संघर्षशील रहेगा. अनेकों बार उतार-चढ़ाव के क्षण आयेंगे. आप अधिक परिश्रम से ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे. आप स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पायेंगे. कोई भी कार्य दूसरों की सलाह से ही करेंगे. दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा. आपका जनसम्पर्क सीमित होने से अकेलेपन की अनुभूति होगी. आप समाज सुधारक एवं आधुनिक प्रकृति के व्यक्ति होंगे. मौजमस्ती के निमित्त अधिक व्यय करेंगे. आपके विचारों में उग्रता का समावेश रहेगा. आप अपने कार्य को ज्यादा महत्व देंगे. धनोपार्जन की ओर रुझान अधिक रहेगा. रचनात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेंगे. आप कार्य को कुशलतापूर्वक नवीनतम तरीके से सम्पन्न करने में सक्षम होंगे. प्रेम प्रसंगों में विफलता ही आपके हाथ लगेगी. सौभाग्य के लिए अपने इष्ट देवी-देवता की पूजा-अर्चना करके घी का दीपक अवश्य जलावें. अपनी आय का कुछ निश्चित प्रतिशत धन गरीबों की सेवा व सहायता में लगावें. अपने दैनिक जीवन में काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग अधिकतम करें. अमावस्या तिथि के दिन गरीबों को भोजन करावें. लाभार्जन का मार्ग प्रशस्त होगा. नशीले पदार्थों से दूर रहें. जीवन में काला, भूरा एवं स्लेटी रंग लाभकारी रहेगा. सफलता के लिए रत्न या उपरत्न तथा यन्त्र विधि-विधानपूर्वक धारण करें. सफलता के लिए रत्न या उपरत्न तथा यन्त्र विधि-विधानपूर्वक धारण करें.

आपके लिए अनुकूल :-

मन्त्र	:	ॐ रां राहुवे नमः	मास	:	फरवरी, जून एवं अगस्त
व्रत	:	शनिवार	वर्ष	:	4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67
दिन	:	सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार	रंग	:	काला, भूरा एवं स्लेटी
दिनांक	:	4, 13, 22, 31	जन्मरत्न	:	गोमेद
उपरत्न	:	काला अकीक	अंक	:	1, 2, 7
जड़ी	:	सफेद चंदन की जड़	दिशा	:	आग्नेय

यंत्र

13	8	15
14	12	10
9	16	11

वर्ष का महत्वपूर्ण समय – 21 मार्च से 28 अप्रैल, 10 जुलाई से 20 अगस्त

हस्तरेखा विशेषज्ञ, रत्न-परामर्शदाता, फलित व अंक ज्योतिषी एवं वास्तुविद

विमल जैन एस. 2/1-76 ए, द्वितीय तल, वरदान भवन, पंचक्रोशी मार्ग, भोजूबीर, वाराणसी-221002 मो0 : 09335414722

आपका आज का दिन 2026

मेष : भाग्योन्नति के नवीन आयाम उपलब्ध, कार्य-व्यवसाय में सफलता, जीवन साथी से सामंजस्य, मनोरंजन में रुचि, प्रेम सम्बन्धों में प्रगाढ़ता, मन प्रसन्न.

वृषभ : आज दिन 7/42 बजे तक अड़चनें, कार्यों में निराशा, आपसी मतभेद, कष्ट, हानि, विवाद, शेष समय में अनुकूलता, साहसिक प्रयास प्रगति पर, भौतिक सुख.

मिथुन : आज दिन 7/42 बजे तक समय संतोषजनक, इच्छा शक्ति का विकास, आर्थिक पक्ष बेहतर, शेष समय में प्रति-कूलता, शारीरिक कष्ट, योजना अधूरी.

कर्क : विचारित कार्यों में प्रगति का सिलसिला, विवाद के समापन से खुशी, पूँजी का प्रतिफल प्राप्त, किसी आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर, संत समागम.

सिंह : अभीष्ट कार्यों में संतोषजनक सफलता, धनागम का सुयोग, धार्मिक क्रियाकलापों में अभिरुचि, सुयश की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता, मौजमस्ती में व्यय.

कन्या : आज दिन 7/42 बजे तक समय अशुभ, आशा अधूरी, लाभ में कमी, स्वजनों से अनबन, शेष समय में दिनचर्या व्यवस्थित, सुसंदेश प्राप्त, पारिवारिक खुशी.

तुला : आज दिन 7/42 बजे तक अनुकूलता, चिरवांछित कार्य पूर्ण, प्रतियोगिता में सफलता, हर्ष भी, शेष समय असंतोष-जनक, कार्यक्षमता का ह्रास, विरोधी प्रभावी.

वृश्चिक : नवयोजना का सुपरिणाम प्राप्त, कुछेक समस्या का समाधान, मांगलिक आयोजन सम्पादित, विवादस्पद मसला हल, आमोद प्रमोद के साधन सुलभ, वाहन का सुख.

धनु : कठिनाइयों के निवारण का मार्ग प्रशस्त, अभिलाषा की पूर्ति, राजकीय पक्ष से सहयोग, दाम्पत्य जीवन मधुर, श्रेष्ठजनों से सम्पर्क का सुयोग, परोपकार की भावना.

मकर : आज दिन 7/42 बजे तक समय विपरीत, व्यवसाय में व्यतिक्रम, समस्याओं से चिन्ता, शेष समय में परिस्थितियाँ सुधार पर, सद्विचारों का उदय, आहार विहार में नवीनता.

कुम्भ: आज दिन 7/42 बजे तक समय शुभ, व्यापार में धन निवेश, शत्रु परास्त, यात्रा सुखद, शेष समय निराशाजनक, पदोन्नति में व्यवधान, एकाग्रता की अभाव.

मीन: व्यावसायिक क्षेत्र में विस्तार, विचारों में जागरूकता, दूसरों के आश्वासनों से मानसिक राहत, किसी के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धि, स्वजनों से तालमेल.

- ज्योतिषाचार्य विमल जैन, वाराणसी, मो. नं. 09335414722

मानव धर्म-शास्त्र

लेखक : लक्ष्मी नारायण मीणा

मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता
अवधूत देवी दास जी महाराज

अष्टम स्कन्ध

जन्मत सुत रां उच्चारी । पीड़ा प्रसव विगत महतारी ।।
चहुँदिसि भयउ प्रकृति उछाहु । मंगल सुगन अनुकूल सबाहु ।।

व्याख्या - जन्म लेते ही पुत्र ने रां नाम का उच्चारण किया, जिससे माता की प्रसव पीड़ा तुरन्त दूर हो गई । चारों तरफ प्रकृति में उत्साह छा गया तथा समस्त मंगलकारी सगुन होने लग गए ।

समाचार सुनि ऋषि सब आए । देखि मुख छवि आशीष बरसाए ।।
बालक ईहैं होइब ब्रम्ह ग्यानी । सकल ऋषि मुनि कहा बखानी ।।

व्याख्या - समाचार सुनकर सब ऋषि आए और बालक की छवि देखकर आर्शीवाद देने लगे । सब ऋषि - मुनियों ने कहा कि यह बालक ब्रम्हज्ञानी होगा ।

सामाजिक समानता का ठोस कदम पीएम स्वनिधि योजना

–डॉ. ओपी त्रिपाठी

रेहड़ी-पटरी विक्रेता, किसी भी शहर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा होते हैं. देश के किसी भी शहर के व्यस्त बाजार में चले जाइए-नुक्कड़ पर चायवाला, ठेले पर सब्जी बेचती महिला या फुटपाथ पर जूते ठीक करता मोची, फटे पुराने कपड़े ठीक करता कारीगर, बाल काटता नाई जरूर दिख जाएगा. ये वही लोग हैं जो सुबह से देर रात तक मेहनत करके हमारी शहरी जिंदगी को चलाते हैं. इनके बिना शहर की रफ्तार थम सी जाएगी, लेकिन इन्हें मुख्यधारा की आर्थिक व्यवस्था में वह जगह नहीं मिल पाई, जिसके वे हकदार थे. पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं दिया, बल्कि उन्हें सम्मान, आत्मविश्वास और एक नई पहचान भी दी है. आजादी के बाद के लंबे कालखण्ड तक इनकी सबसे बड़ी समस्या यह रही कि बैंक से आसान लोन नहीं मिलता था. मजबूरी में ये लोग ऊंचे ब्याज वाले अनौपचारिक कर्ज पर निर्भर रहते थे, जिससे कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता था. इसी स्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जून 2020 को 'पीएम स्वनिधि' योजना शुरू की. इस योजना ने अब छह साल पूरे कर लिए हैं .शहरों की गलियों से लेकर कस्बों तक, पीएम स्वनिधि ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है. अब रेहड़ी-पटरी वाले सिर्फ रोजगार नहीं चला रहे, बल्कि औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनकर सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं. उनकी सामाजिक और आर्थिक पहचान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है. पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सिर्फ वित्तीय सहायता देना नहीं था, बल्कि रेहड़ी-पटरी वालों को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान से जोड़ना था. यह योजना शहरी गरीबों को सम्मान और अवसर दोनों देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी गई. कोरोना महामारी के समय शुरू हुई यह योजना आज करोड़ों परिवारों की आजीविका का सहारा बन चुकी है. इसके मजबूत प्रभाव को देखते हुए मोदी सरकार ने इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है, जिससे साफ है कि यह पहल अब लंबे समय तक शहरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा रहने वाली है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लाखों छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है. कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 75.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 112 लाख से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं. सरकार ने योजना की सफलता को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाकर मार्च 2030 तक कर दी है. योजना के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वाले विक्रेताओं को बिना गारंटी 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है. समय पर कर्ज चुकाने वालों को 7 फीसदी वार्षिक ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलता है और वे अगले चरण में अधिक राशि के ऋण के पात्र बन जाते हैं. सरकार के अनुसार, देशभर में अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है. इसके अलावा लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी और डिजिटल कैशबैक के रूप में करीब 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा मिला है. योजना के तहत तीन चरणों में लोन उपलब्ध कराया जाता है-15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये तक. समय पर भुगतान करने पर ब्याज सब्सिडी और आगे बड़े लोन का अवसर मिलता है, जिससे छोटे कारोबारियों को अपना काम बढ़ाने में मदद मिल रही है. यह मॉडल छोटे व्यापार को धीरे-धीरे मजबूत बनाने पर आधारित है. पीएम स्वनिधि ने डिजिटल भारत की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया है. अब रेहड़ी-पटरी वाले भी यूपीआई और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका कारोबार ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो गया है. नकद पर निर्भरता कम होने से उनकी आर्थिक व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हुई है. करीब 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ा गया है और उनके जरिए 841 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनका मूल्य लगभग 8.96 लाख करोड़ रुपये है. यह आंकड़ा बताता है कि यह योजना सिर्फ कर्ज देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है. डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जिसके तहत विक्रेताओं को साल में 1,600 रुपये तक का लाभ मिलता है. इसके अलावा ब्याज सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे हैं, जिससे उनकी आय पर सकारात्मक असर पड़ा है. दूसरे चरण का लोन चुकाने के बाद वेंडर्स को यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, जिसकी सीमा 30,000 रुपये तक होती है. यह कार्ड आपातकालीन जरूरतों और थोक खरीद में मदद करता है, जिससे छोटे व्यापारियों की आर्थिक निर्भरता कम होती है और उन्हें तुरंत वित्तीय सहारा मिल जाता है. इस योजना का एक बड़ा असर महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में सामने आया है. अब तक 34.81 लाख महिला रेहड़ी-पटरी वालों को इसका लाभ मिला है, यानी इस योजना के कुल लाभार्थियों में से एक बड़ा हिस्सा लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं हैं. इससे शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों बढ़ी हैं. करीब 70 प्रतिशत लाभार्थी समाज के हाशिए पर रहने वाले कमजोर वर्गों से आते हैं, जिससे यह साफ होता है कि योजना का फोकस समावेशी विकास पर रहा है. यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में भी एक मजबूत कदम है. लाभार्थियों की औसत आय में लगभग 20 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर्ज की गई है. इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है और वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पा रहे हैं. कई लोग अब अपने छोटे कारोबार का विस्तार भी कर रहे हैं. योजना का असर जमीन पर साफ दिखाई देता है. लगभग 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने पहली बार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण लिया. जिससे उनकी वित्तीय साख मजबूत हुई है. करीब 30 प्रतिशत लोगों ने बाद में अतिरिक्त ऋण लेकर अपने व्यवसाय को और बढ़ाया, जो उनके आर्थिक आत्मविश्वास को दर्शाता है. स्वनिधि से समृद्धि'पहल के तहत लाभार्थियों और उनके परिवारों को आठ प्रमुख सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है. इससे पूरा परिवार एक मजबूत सुरक्षा कवच के दायरे में आ रहा है और जीवन अधिक स्थिर हो रहा है. इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता और डिजिटल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जा रहा है. एफ.एस.एस.ए.आई. के सहयोग से स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे छोटे विक्रेताओं के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ी है और ग्राहकों का भरोसा मजबूत हुआ है. पीएम स्वनिधि योजना शहरी विकास की सोच में बड़े बदलाव का संकेत देती है, जहां छोटे विक्रेताओं को अब हाशिए पर नहीं बल्कि विकास के साझेदार के रूप में देखा जा रहा है. यह बदलाव भारत के समावेशी और आत्मनिर्भर विकास मॉडल को और मजबूत करता है. यह छह साल की यात्रा दिखाती है कि सही नीति, भरोसा और अवसर मिलें तो छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं. असल में जब हाशिए पर खड़े लोग और उपेक्षित वर्ग आर्थिक तौर पर सशक्त होगा तो विकसित भारत का सपना साकार होने में देर नहीं लगेगी. ***(चिकित्सक एवं लेखक)***

न्यूज कॉर्नर

जामाडोबा में बंद पड़े रोप-वे के ढांचे को हटाया

धनबाद : जिले में बंद पड़े पुराने रोप-वे और लोहे के परित्यक्त ढांचों को हटाने की मुहिम तेज कर दी गई है. उपायुक्त के निर्देश के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने विभिन्न क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े रोप-वे को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है.इसी क्रम में बुधवार को झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत जामाडोबा डुमरी 2 नंबर में बंद पड़े रोप-वे के लोहे के ढांचे को काटकर हटाया गया. कार्रवाई के दौरान बीसीसीएल अधिकारियों के साथ सीआईएसएफ और जोड़ापोखर थाना की पुलिस भी मौजूद रही. सुरक्षा व्यवस्था के बीच मशीनों और गैस कटर की सहायता से जर्जर एवं अनुपयोगी लोहे के ढांचों को हटाया गया.सुरक्षा को लेकर सड़क के दोनों ओर बैरीकेडिंग कर दी गई थी. सीआईएसएफ और जोड़ापोखर थाना की पुलिस भी मौजूद थी. उन्होंने कहा कि बंद पड़े इन लोहे के ढांचों से सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा था. स्थानीय लोगों ने भी जिला प्रशासन की इस मुहिम की प्रशंसा की. लोगों ने कहा कि बंद पड़े लोहे के इन ढांचों को हटाने से न केवल चोरी बल्कि दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा. क्षेत्र में कानून-व्यवस्था भी बनी रहेगी. वहीं उपायुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में जिले के अन्य क्षेत्रों में स्थित ऐसे परित्यक्त ढांचों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा.

राधेश्याम गोस्वामी ने वृद्धाआश्रम में मनाया अपना जन्मदिन

धनबाद :सबलपुर सहयोगी नगर स्थित ओल्ड ऐज होम वृद्धाआश्रम में धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने अपना जन्मदिन बुजुर्गों के संग केक काट कर मनाया. इस मौके पर धनबाद कोर्ट के कई अधिवक्ता और अतिथि मौजूद थे.अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने इस मौके पर कहा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच जन्मदिन मनाना एक बेहद अनूठा अनुभव देता है, बल्कि बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाकर उनके जीवन में नई खुशियां भर देता है. उन्होंने लगातार वृद्धा सेवा आश्रम प्रबंधन को आश्रम की स्थापना के पुण्य कार्य के लिए बधाई दी. जन्मदिन पर भावुक होते हुए कहा कि मेरे माता-पिता नहीं है लेकिन आश्रम आकर के यहां आश्रित बुजुर्ग माता पिता की सेवा सम्मान करके जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद लेना बहुत सौभाग्य की बात है. बुजुर्गों की सेवा को ईश्वरीय कार्य बताते हुए उन्होंने सभी युवाओं को संदेश दिया कि अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा करें क्योंकि एक दिन वे भी बूढ़े होंगे और उन्हें भी सेवा सहायता की जरूरत होगी. ओल्ड ऐज होम में बुजुर्गों के लिए स्वादिष्ट और सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई थी जिसे खुद राधेश्याम गोस्वामी ने अपने हाथों से स्नेह पूर्वक परोसकर खिलाया. बुजुर्गों ने इस सेवा सम्मान के लिए राधेश्याम गोस्वामी सहित उपस्थित सभी को अपना हार्दिक आशीर्वाद दिया. इस मौके पर अधिवक्ताओं में बिजेंद्र कुमार सिंह, नचिकेता गोस्वामी, राहुल गोस्वामी, इमरान खान, खालिद, विजय गोराई,संजीत महतो, राजीव गोस्वामी, शिवशंकर गोस्वामी, लक्ष्मी नारायण गोस्वामी, अमित मंडल, महिला अधिवक्ताओं में संजू सिंह,अनंता तिवारी, संध्या, प्रीति जायसवाल समेत अन्य अतिथि उपस्थित थे.

एसडीओ की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर बैठक

उधवा : प्रखंड कार्यालय कक्ष में बुधवार को एसआईआर को लेकर एसडीओ राजमहल सदानंद महतो की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ जयंत कुमार तिवारी एवं पर्यवेक्षक मौजूद रहे. इस दौरान एसडीओ सदानंद महतो ने एसआईआर के पुनरीक्षण एवं अनमैप्ड मतदाताओं को लेकर पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अनमैप्ड मतदाता सूची की मैपिंग नहीं हो पाया है. वैसे मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर अपने बीएलओ से संपर्क करें और मैपिंग का कार्य पूर्ण कराएं. ताकि कोई भी वैध मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाएं. मौके पर निर्वाचन नोडल सूरज टुडू,पर्यवेक्षक संतोष कुमार सुमन,ओमप्रकाश साहा,मोनिका मुर्मू,सत्यनारायण रजवार,उदय कुमार मंडल,गिरिधारी मंडल सहित अन्य मौजूद थे.

एस आई आर मैपिंग कार्य 15 जून तक पूरा करने का निर्देश

तालझारी : प्रखंड सभागार में बुधवार को नोडल नवीन कुमार के अध्यक्षता में एसआईआर से संबंधित सभी बीएलओ सुपरवाइजरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में उपस्थित सभी कर्मियों को एसआईआर कार्य से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्य को सुचारू रूप से करने की विस्तृत जानकारी दी गई.बैठक में स्पष्ट किया गया कि जब तक एसआईआर का कार्य चलेगा, तब तक सभी बीएलओ, सुपरवाइजर एवं इससे जुड़े अन्य कर्मियों की छुट्टियां स्थगित रहेंगी.15 जून के बाद बंद हो जाएगा मैपिंग का कार्यबैठक में कड़े निर्देश देते हुए कहा गया कि हर हाल में 15 जून से पहले मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया जाए. 15 जून के बाद मैपिंग का पोर्टल या कार्य बंद हो जाएगा. सभी कर्मियों को ऐप के माध्यम से मैपिंग और विसंगति की एक सूची बनाने को कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस मतदाता का काम अधूरा रह गया.बीडीओ जारी करेंगे नोटिस, ग्राम सभा में होगा फैसलालिस्टिंग का कार्य पूरा होने के बाद, जिन मतदाताओं की मैपिंग या विसंगति का सुधार नहीं हो पाया है, उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद उन सभी मतदाताओं के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा. ग्राम सभा में तय 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, यदि मतदाता मैपिंग के योग्य पाया जाता है, तो उसका कार्य पूरा किया जाएगा. मौके पर बीएलओ सुपरवाइजर राजेंद्र मंडल, मिथिलेश कुमार पांडे, मो. रिजवान, जयप्रकाश मंडल सहित अन्य उपस्थित थे.

श्रावणी मेले को राजकीय दर्जा दिलाने की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

युवाशक्ति न्यूज
विद्यापतिनगर: मिथिलांचल के प्रसिद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर श्री बालेश्वर स्थान विद्यापतिधाम मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले श्रावणी मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मंदिर न्यास समिति एवं सामाजिक प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल पटना में बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से बुधवार को मिला. प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपते हुए विद्यापतिधाम की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्ता से अवगत कराया. शिष्टमंडल मे श्री बालेश्वर स्थान (विद्यापतिधाम) मंदिर न्यास समिति के कोषाध्यक्ष रत्न शंकर भारद्वाज ,यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष पदमाकर सिंह लाला,कार्यकारी अध्यक्ष राजा सिंह,चंदन कुमार भोला,ऋतिक कुमार भी मौजूद रहे.प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि विद्यापतिधाम को मिथिलांचल का देवघर कहा जाता है. यह स्थल भक्त और भगवान के मिलन की पावन भूमि के रूप में प्रसिद्ध है. मान्यता है कि महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान

शिव यहां प्रकट हुए थे. इसी कारण यह मंदिर मिथिला ही नहीं, बल्कि बिहार और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.

श्रावण मास में यहां लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.

बावजूद इसके मेले को अब तक राज्यकीय दर्जा नहीं मिल सका है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राजकीय मेला घोषित होने से यहां आधारभूत सुविधाओं पेयजल, शौचालय, स्नानागार, चिकित्सा शिविर एवं एम्बुलेंस सेवा, पर्याप्त पुलिस बल, महिला सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल, यातायात नियंत्रण, अस्थायी विश्राम स्थल, जगह-जगह तोरण द्वार तथा सूचना एवं सहायता केंद्र के साथ ही कावरियों के लिए सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मांग को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित स्तर पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया. प्रतिनिधिमंडल ने आशा जताई कि सरकार विद्यापतिधाम की ऐतिहासिक पहचान और जनभावनाओं को देखते हुए इस मांग पर शीघ्र निर्णय लेगी.

गया जिला में 1 जुलाई से डिग्री कॉलेज रहित 7 प्रखंडों में पढ़ाई शुरू होगी

युवा शक्ति न्यूज
गया : राज्य सरकार के आदेश के आलोक में गया जिला में 1 जुलाई से डिग्री कॉलेज रहित 7 प्रखंडों- अतरी, नीमचक बथानी, कोच, मोहड़ा, बाकेबजार, डुमरिया एवं मोहनपुर में उत्सवी माहौल में डिग्री की पढ़ाई शुरू होगी. इस संबंध में जिले के डीएम शशांक शुभंकर द्वारा बुधवार को सभी संबंधित अनुमंडलों के एसडीओ, मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, नव-नियुक्त प्राचार्यों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, भवन, विद्युत, पीएचईडी, एलएईओ सहित विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं, सभी सातों बीडीओ, बीईओ एवं अन्य के साथ इसकी तैयारियों की वृहत समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई तथा पदाधिकारियों को सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आपस में समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुदृढ़ व्यवस्था करने का निदेश दिया गया.डीएम ने कहा कि राज्य सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम के चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा-उज्जवल भविष्य के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है.इसी क्रम में 1 जुलाई से राज्य के डिग्री कॉलेज रहित 211 प्रखंडों में डिग्री की पढ़ाई शुरू की जा रही है.इसमें गया जिला के उपर्युक्त 7 प्रखंड भी शामिल है.आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है.पूरे भव्य, उत्साह एवं उत्सवी माहौल में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू की जाएगी.डीएम ने कहा कि वर्तमान में इन डिग्री कॉलेजों के संचालन हेतु अस्थायी तौर पर भवनों का चयन किया गया है.इन भवनों में सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी.इसके लिए आज संबंधित पदाधिकारी के साथ विस्तार से समीक्षा की गई है.ज़िला स्तरीय अपर समाहर्ता गण की अध्यक्षता में हर डिग्री कॉलेज के लिये कमिटी बनाया गया है, साथ ही सभी एसडीओ को संबंधित प्राचार्यों एवं शिक्षा विभाग के जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों के साथ भवनों का स्वयं निरीक्षण करने का निदेश दिया गया है.डीएम ने कहा कि इन डिग्री कॉलेजों के सुचारू रूप से संचालन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.पदाधिकारियों को विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुरूप फर्नीचर/उपस्कर, कम्प्यूटर, वाईफाई, अस्थायी संचालन हेतु चयनित भवनों की मरम्मति, रंग-रोगन, शुद्ध पेयजल, वाटर कूलर, आरओ, महिला एवं पुरूष के लिए अलग शौचालय, बिजली, प्रकाश, पंखा, कूलर, एसी, स्टेशनरी आइटम्स, कॉलेज आने के रास्ते को सुगम रखना, परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई सहित अन्य सभी प्रबंध वित्तीय नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करने का निदेश दिया गया है.उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.

पदाधिकारीगण इसे सुनिश्चित करें.डीएम ने कहा कि इन डिग्री कॉलेज के स्थायी भवनों हेतु जिला प्रशासन द्वारा समयबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है.

सरकार के निदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 5 एकड़ तथा नगर क्षेत्रों में न्यूनतम 2.5 एकड़ जमीन खोजने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.डीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.इसके लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है.बैठक में डीडीसी, एडीएम राजस्व/आपदा/ विधि व्यवस्था/ विभागीय जांच, डीईओ, सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

पूर्व रक्षा मंत्री स्व.जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर मंत्री श्रवण कुमार ने दी श्रद्धांजलि

युवाशक्ति न्यूज
पटना:मुजफ्फरपुर स्थित सिटी पार्क में पूर्व केन्द्रीय रक्षा मंत्री, प्रखर समाजवादी नेता,सर्वोच्च नागरिक सम्मान ''पद्म विभूषण' से सम्मानित श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस की जयन्ती राजकीय समारोह के रूप में गरिमामय वातावरण में मनाई गई. इस अवसर पर श्रवण कुमार, मंत्री,ग्रामीण विकास व सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग सह नेता विधायक दल ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया. माननीय मंत्री के साथ मीनापुर के विधायक, अजय कुमार,रून्नी सैदपुर के विधायक,पंकज मिश्रा ने भी पुष्प माला अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.इस अवसर पर जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर, सुब्रत कुमार सेन, पुलिस अधीक्षक, कंटेश कुमार,उप विकास आयुक्त, श्रेष्ठ अनुपम, नगर आयुक्त, ऋतुराज प्रताप सिंह, उप समाहर्ता विधि व्यवस्था सह विशेष कार्य पदाधिकारी सुधीर कुमार सिन्हा, जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, प्रमोद कुमार सहित जिला के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. माननीय मंत्री श्रवण कुमार, श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के करीबियों में से एक थे. वे उनके राष्ट्र निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित जीवन को याद करते हुये श्री कुमार ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब एक निर्भीक और जनप्रिय नेता थे. जिन्होंने आपात काल के विरोध से लेकर, उद्योग, रेल तथा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय तक, पोखरण-2 सफल परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध विजयी जैसे अनेक देश की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने बाली ऐतिहासिक भूमिकाएँ को राष्ट्र कभी भूल नहीं सकती.श्री कुमार ने कहा कि उनका सम्पूर्ण जीवन, लोकतंत्र, सामाजिक समानता और जनसेवा के आदर्शो का प्रतीक रहा है.

अवैध खनन, विरूद्ध छापेमारी

युवा शक्ति न्यूज
गया : जिले के डीएम शशांक शुभंकर के निदेशानुसार अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डरण के विरूद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है.इस कड़ी में खनिज विकास पदाधिकारी नवेंदु सिंह के द्वारा बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के माह-अप्रैल, 2026 एवं मई, 2026 में जिलान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध 281 छापेमारी की गई है, जिसमें अवैध खनिकर्म में संलिप्त कुल 93 वाहनों को विधिवतब जप्त करते हुए

सबंग में छात्रा से बदसलूकी का मुख्य आरोपित पीटी शिक्षक गिरफ्तार, कुल सात पकड़े गए

पश्चिम मेदिनीपुर : जिले की सबंग थाना पुलिस ने दसवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में मुख्य आरोपित और स्कूल के पीटी शिक्षक प्रसून बेरा को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस अब तक दो नाबालिगों समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना के बाद से ही आरोपित शिक्षक लगातार फरार चल रहा था. बुधवार दोपहर पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैक कर नारायणगढ़ थाना इलाके से उसे धर दबोचा. आरोपित शिक्षक को गुरुवार को पॉक्सो (पॉक्सो) अदालत में पेश किया जाएगा.कॉल रिकॉर्ड के जरिए पकड़ा गया आरोपित शिक्षक पश्चिम मेदिनीपुर की पुलिस अधीक्षक (एसपी) पापिया सुल्ताना ने एक पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए कहा कि इस घृणास्पद घटना में संलिप्त दो नाबालिगों समेत छह आरोपितों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. मुख्य आरोपित शिक्षक पुलिस को चकमा देकर भागा-भागा फिर रहा था. बुधवार को कॉल डिटेल्स और टावर लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपितों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.एसपी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि जहां शिक्षक के पास छात्र-छात्राएं सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां ऐसी हरकत बेहद निंदनीय है.मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्रा ने गत 12 मई को सबंग थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, 11 मई की दोपहर जब वह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी रास्ते में पांच-छः छात्रों ने उसे घेर लिया

पीसीसी सड़क को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है

युवा शक्ति न्यूज
गया : प्रदेश में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत शहरों कस्बों के आधुनिकीकरण का दावा किया गया था. जो अब दम तोड़ रहा है.स्थानीय प्रशासन और कार्यदायी संस्था 'बुडको की लापरवाही के चलते एक अच्छी पीसीसी सड़क को तोड़कर उसे फिर से बनाने का 'खेल' खेला जा रहा है, जिससे न केवल जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, बल्कि आम नागरिकों का जीना भी दूभर हो गया है.वीडियो में एक वार्ड पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह ग्राउंड जीरो से इस बदहाली की पोल खोलते नजर आ रहे हैं.उनके मुताबिक, पिछले दो महीनों से इस मुख्य सड़क को पूरी तरह से तोड़कर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है.सड़क की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वहां बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें गंदा पानी भरा हुआ है.दोपहिया वाहन चालक और राहगीर रोजाना इस कीचड़ और मलबे से होकर गुजरने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है.तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे सड़क के किनारे मलबे और पत्थरों को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया गया है.नाली निर्माण और पाइपलाइन के नाम पर जो गड्ढे खोदे गए थे.उन्हें भी सही तरीके से दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके चलते बारिश का पानी और नालियों का गंदा पानी सड़क पर ही जमा हो रहा है.मामले में सबसे बड़ा सवाल वित्तीय अनियमितता और बिना सोचे-समझे बनाई गई योजना पर खड़ा होता है.पार्षद का कहना है कि जो सड़क पहले से ही पक्की और मजबूत थी.उस पर मात्र 10 लाख रुपए खर्च करके एक बेहतरीन पिच (डामर की परत) बनाई जा सकती थी, लेकिन अधिकारियों ने इस आसान और किफायती रास्ते को छोड़कर पूरी मजबूत सड़क को 14 इंच गहराई तक तुड़वा दिया.अब इस तोड़ी गई सड़क को दोबारा बनाने के लिए 82 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है.पार्षद का कहना है कि जब 10 लाख रुपए में सड़क चकाचक हो सकती थी, तो जनता की गाढ़ी कमाई के 82 लाख रुपए इस तरह क्यों फूंके जा रहे हैं. वार्ड पार्षद ने एक और बेहद गंभीर और व्यावहारिक मुद्दे की तरफ वीडियो के माध्यम से सरकार व आम अवाम का ध्यान आकर्षित किया है.उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के लिए पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है,

सौंदर्यीकरण एवं हरित विकास को लेकर समीक्षा बैठक, गुणवत्तापूर्ण कार्य पर दिया गया जोर

युवा शक्ति न्यूज
गया : बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बुधवार को गयाजी जिला अतिथि गृह सभागार में नगर निगम के अधिकारियों के साथ शहर के सौंदर्यीकरण, हरित विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की.बैठक में शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.बैठक के दौरान डॉ. प्रेम कुमार ने एपीआर मोड़, मिर्ज़ा गालिब मोड़, आशा सिंह मोड़ तथा समाहरणालय के सामने निर्माणाधीन गोलंबरों के सौंदर्यीकरण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ किए जाएं तथा उनमें गयाजी की पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखाई देनी चाहिए.अधिकारियों ने जानकारी दी कि सीताकुंड क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है.इसके अतिरिक्त केदारनाथ मार्केट, सिकड़िया मोड़ एवं कठोकर तालाब के निकट वेंडिंग जोन के लिए अतिरिक्त सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का विकास किया जा रहा है.बैठक में बताया गया कि शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गया टाउन क्षेत्र के जिलाधिकारी आवास, जज कंपाउंड, जेपी थाना, गांधी मैदान, एपीआर0 के सामने वाली दीवाल, दिग्गी तालाब के पास, सिविल लाइन थाना, जुडियो के सामने, रामशिला एंट्री पॉइंट, विसार तालाब, सीता कुंड रबर डैम के पास, रामसागर तालाब के दीवार के पास, ब्रह्मसत्य तालाब, रुकमणी तालाब, बाईपास, नारायणी पुल, सिकरिया मोड़ बस स्टैंड, गेवल बीघा, खलीज पार्क, सिक्स लेन ब्रिज के एंट्री के पास, चांदचौरा विष्णुपद रोड, रेलवे स्टेशन, निगम स्टेशन, मगध मेडिकल कंपाउंड, डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास, जोड़ा मस्जिद गोलंबर के पास, सूर्य पोखर ऐसे 25 स्थानों को वर्टिकल प्लांटेशन के लिए चिन्हित किया गया है.कई स्थानों पर कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा शेष स्थलों पर भी शीघ्र कार्य शुरू किया जाएगा.डॉ प्रेम कुमार ने एटी गेट एवं जिला अतिथि गृह के सामने सौंदर्यीकरण कार्य की सराहना की साथ ही उन्हें धन्यवाद व्यक्त किया.डॉ. प्रेम कुमार ने निर्देश दिया कि शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर आकर्षक प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जाए तथा व्यापक स्तर पर हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाए.उन्होंने पथ निर्माण विभाग की भूमि के अतिरिक्त उपलब्ध खाली स्थलों पर सड़क किनारे लोहे के गेबियन लगाकर वृक्षारोपण करने एवं हरियाली विकसित करने का निर्देश दिया.बैठक में गयाजी नगर क्षेत्र के सभी घाटों, तालाबों, पार्कों एवं गोलंबरों के समग्र सौंदर्यीकरण एवं हरियाली विकास पर विशेष जोर दिया गया.डॉ. प्रेम कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सभी स्थलों के विकास का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से अविलंब उपलब्ध कराया जाए, ताकि योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके.उन्होंने कहा कि गयाजी विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन नगरी है.इसके अनुरूप शहर को स्वच्छ, सुंदर, हरित एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.वहीं मौके पर राजनंदन गांधी, अमित लोहानी, बंटी वर्मा, धीरेंद्र धीरू, राकेश आईटी, रॉकी चंद्रवंशी, विवेक कुमार, सचिन ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत नव नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों का भव्य स्वागत

धनबाद : उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत नव नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन (अभिमुखीकरण) कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल सभागार में किया गया. कार्यक्रम में एनएचएम के तहत चयनित 120 नव नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया गया तथा उन्हें स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियों एवं जनसेवा के मूल्यों से अवगत कराया गया.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (छकच) के तहत संविदा आधारित भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए जिले में विभिन्न 18 पदों पर कुल 120 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है. इन पदों के लिए कई उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसके बाद लिखित परीक्षा और सफल अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट आयोजित किया गया.

चयनित अभ्यर्थियों में एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैबोरेट्री टेक्नीशियन सहित कई स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं.

इन स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती सदर अस्पताल के साथ-साथ जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की जाएगी, जिससे ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी.

इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी नव नियुक्त कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी पदस्थापना हो, वहां समय पर उपस्थित रहकर पूरी

ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें तथा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं.

उपायुक्त ने अपने संबोधन में "ABCD की चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को अपने कार्य में इन चार मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिएङ्ग

उन्होंने इन चारों बिंदुओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि एक सफल एवं जनहितैषी स्वास्थ्यकर्मी बनने के लिए इन मूल्यों को अपने कार्य व्यवहार में शामिल करना आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई है तथा जल्द ही सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट कहा कि ज्वाइनिंग या नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की घूस या अवैध राशि की मांग करता है तो अभ्यर्थी तत्काल उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक या उप विकास आयुक्त से संपर्क करें.

उपायुक्त ने यह भी बताया कि आगामी चरण में पुनः लगभग 100 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित की जाएगी. जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं लेकिन मेरिट सूची में स्थान नहीं बना सके हैं, उन्हें प्राथमिकता देने पर विचार किया जाएगा.

वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सभी नव नियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र केवल नौकरी नहीं बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम है. उन्होंने कर्मियों से संवेदनशीलता, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया तथा कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा.

उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की गई है. उन्होंने नव नियुक्त कर्मियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की जानकारी देते हुए कहा कि नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें, अन्यथा वेतन भुगतान प्रभावित हो सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस केंद्र या क्षेत्र में पदस्थापना दी जाए, वहां समय पर योगदान देना अनिवार्य होगा. बिना योगदान के पदस्थापना निरस्त की जा सकती है.

इस अवसर पर कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, सिविल सर्जन सहित जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे.

भारत बनाम न्यूजीलैंड ऑल-फॉर्मेट सीरीज का ऐलान, रोहित-कोहली की मैदान पर वापसी

नयी दिल्ली: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 3 जून को भारत और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया. भारत का दौरा अक्टूबर-नवंबर 2026 में होगा, जिसमें दोनों टीमें पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेंगी. खास बात यह है कि वनडे सीरीज को तीन मैचों से बढ़ाकर पांच मैचों का कर दिया गया है. यह दौरा रोहित शर्मा और विराट कोहली का 2027 वनडे विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड का आखिरी दौरा हो सकता है. दोनों दिग्गज नवंबर में होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी. पहला और दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच वेलिंग्टन, चौथा ऑकलैंड और पांचवां मुकाबला हैमिल्टन में आयोजित होगा. टी20 सीरीज का समापन 1 नवंबर को हैमिल्टन में होगा, जिसके बाद दोनों टीमें वनडे

सीरीज में भिड़ेंगी. वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर को ऑकलैंड में होगी. दूसरा वनडे 7 नवंबर को वेलिंग्टन, तीसरा 10 नवंबर को हैमिल्टन, जबकि चौथा और पांचवां मुकाबला 13 और 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेला जाएगा. वनडे विश्व कप 2027 को देखते हुए यह सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव पर एक बार फिर टीम की नजरें होंगी. टी20 और वनडे सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंग्टन में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से बेहद अहम होगी. न्यूजीलैंड दौरा भारत के डूब्ल्यूटीसी अभियान के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा.

भारत के न्यूजीलैंड दौरे का पूरा कार्यक्रम : (टी20 सीरीज) : पहला टी20 - 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च. दूसरा टी20 - 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च. तीसरा टी20- 27 अक्टूबर, वेलिंग्टन. चौथा टी20 - 30 अक्टूबर, ऑकलैंड. पांचवां टी20 - 1 नवंबर, हैमिल्टन. **(वनडे सीरीज) :** पहला वनडे - 4 नवंबर, ऑकलैंड. दूसरा वनडे - 7 नवंबर, वेलिंग्टन. तीसरा वनडे - 10 नवंबर, हैमिल्टन. चौथा वनडे - 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई. पांचवां वनडे - 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई. **(टेस्ट सीरीज) :** पहला टेस्ट - 19-23 नवंबर, वेलिंग्टन. दूसरा टेस्ट - 27 नवंबर-1 दिसंबर, क्राइस्टचर्च.

पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे 400 से ज्यादा एथलीट

अहमदाबाद: पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में 60 से ज्यादा देशों के 400 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे जो बृहस्पतिवार से यहां शुरू हो रही है. विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के पहले चरण में अमेरिका, घाना, कीनिया, मलेशिया, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान समेत दुनिया भर के एथलीट हिस्सा लेंगे. यह ऐतिहासिक चैंपियनशिप योगासन के विकास में एक अहम मोड़ है जो भारत के योग को दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी खेल के तौर पर बदल रहा है और साथ ही ओलंपिक मूवमेंट में पहचान दिलाने का रास्ता भी मजबूत कर रहा है. विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 को खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, गुजरात खेल प्राधिकरण, गुजरात पर्यटन और गुजरात योगासन खेल संघ का समर्थन प्राप्त है. मेजबान भारत 122 लोगों का दल उतारेगा जिसमें एथलीट छह वर्ग में मुकाबला करेंगे. ये एथलीट पांच दिन में व्यक्तिगत स्पर्धा और कलात्मक स्पर्धा में अपना कौशल दिखाएंगे और वैश्विक स्तर पर पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग प्रणाली शुरू की जाएगी जिससे पारदर्शिता, निरंतरता और जजों का स्तर बेहतर होगा.

अंडर-18 पुरुष एशिया कप हॉकी

चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर भारत सेमीफाइनल में

काकामिगाहारा (जापान): भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बुधवार को यहां अपने आखिरी पूल ए मैच में चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया और अंडर-18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाई. भारत ने कजाखस्तान, कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाफ जीत के साथ अपने पूल मैच खत्म किए जबकि मेजबान जापान से उसे हार का सामना करना पड़ा. इससे टीम को चार मैच में नौ अंक मिले. चीनी ताइपे के खिलाफ टीम ने आक्रामक रूख अपनाया जिसमें आशीष तानी पूर्ति ने हैट्रिक (27वें, 35वें, 42वें मिनट) करके सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जबकि गाजी खान (40वें, 44वें), सिद्धार्थ बेन (30वें, 52वें) और राहुल यादव (20वें, 54वें) ने दो-दो गोल किए. करण गौतम (सातवें), प्रेमचंद सोय (11वें), कप्तान केतन कुशवाहा (13वें) और वरिंदर सिंह (50वें) ने भी गोल किए. भारत शुक्रवार को अपना सेमीफाइनल खेलेगा लेकिन टीम के प्रतिद्वंद्वी का फैसला बुधवार को जापान और कजाखस्तान के बीच पूल ए के आखिरी मैच के बाद होगा.

एशियाई रिले चैंपियनशिप में गुरविंदरवीर सिंह करेंगे भारतीय दल की अगुवाई

नयी दिल्ली: पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरविंदरवीर सिंह 20 और 21 जून को चीन के शांग्यू में होने वाली दूसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत की 29 सदस्यीय मजबूत टीम की अगुआई करेंगे. भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) के अध्यक्ष बहादुर सिंह ने बताया कि एएफआई द्वारा चुनी गई भारतीय टीम के सदस्य सभी छह रिले स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा, ''चीन में होने वाली यह प्रतियोगिता एथलीटों के लिए महाद्वीपीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा मौका होगी.'' एशियाई रिले चैंपियनशिप का तीसरा सत्र चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा. हाल ही में हांगकांग में हुई एशियाई एथलेटिक्स संघ की परिषद की बैठक में इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी भारत को सौंपी गई थी. चीन में होने वाली इस प्रतियोगिता में पुरुषों की चार गुणा 100 मीटर और चार गुणा

400 मीटर रिले तथा महिलाओं की चार गुणा 100 मीटर और चार गुणा 400 मीटर रिले स्पर्धाएं शामिल होंगी. इसके अलावा भारतीय टीम मिश्रित चार गुणा 100 मीटर और चार गुणा 400 मीटर रिले स्पर्धाओं में भी हिस्सा लेगी.

एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम : पुरुष (चार गुणा 400 मीटर और मिश्रित चार गुणा 400 मीटर रिले): तीर्थेश पी शेट्टी, अविनाश कुमार, सेतु मिश्रा, निहाल विलियम, एस संतोष, रिंस जोसेफ, सूरज अलगर राजा, मोहित कुमार, बराथ श्रीधर. **पुरुष (चार गुणा 100 मीटर और मिश्रित चार गुणा 100 मीटर रिले):** अनिमेष कुजूर, गुरिंदरवीर सिंह, हर्ष संतोष राउत, प्रणव प्रमोद गौरव, रागुल कुमार गणेश कुमार, सेंथिल कुमार तमिलरासु. **महिला (चार गुणा 400 मीटर और मिश्रित चार गुणा 400 मीटर रिले):** रशदीप कौर, पूवम्मा एमआर, अंसा बाबू, विजयकुमारी जीके, सलोनी नागर, नीरू पाठक, सुभा वी, गौरीनंदना. **महिला (चार गुणा 100 मीटर और मिश्रित चार गुणा 100 मीटर रिले):** नित्या गंधे, तमन्ना, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर, अबिनया राजराजन.

बालाजी और डेमोलिनर की जोड़ी फ्रेंच ओपन से बाहर

पेरिस: भारतीय टेनिस खिलाड़ी एन श्रीराम बालाजी और ब्राजील के उनके जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर का फ्रेंच ओपन पुरुष युगल में शानदार प्रदर्शन क्वार्टर फाइनल में हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से सीधे सेटों में हार के साथ खत्म हो गया. बालाजी और डेमोलिनर की जोड़ी एक घंटे 17 मिनट तक चले मुकाबले में 3-6, 4-6 से हार गई. हार के बावजूद बालाजी और डेमोलिनर की जोड़ी के लिए टूर्नामेंट में प्रदर्शन यादगार रहेगा क्योंकि वे तीसरे दौर में जर्मनी के केविन क्राविएट्ज और टिम पुट्ज की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 7-5, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे. बालाजी के लिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचना उनके करियर के सबसे अच्छे ग्रैंड स्लैम प्रदर्शनों में से एक है और युगल सर्किट में उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है. अर्णव पापरकर लड़कों के एकल के तीसरे दौर में हार गए जबकि माया राजेश्वरन रेवती लड़कियों के एकल के दूसरे दौर में पराजित हो गईं. लड़कों के युगल में पापरकर की चुनौती अभी बरकरार है. वह थाईलैंड के अपने जोड़ीदार कुनानन पेंटारेटॉर्न के साथ ब्राजील के लुइस गुटो मिगुएल और स्लोवेनिया के जिागा सेस्को की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से भिड़ेंगे.

आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में, सात्विक-चिराग मैच से हटे

जकार्ता : युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बुधवार को यहां इंडोनेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई जबकि सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष युगल जोड़ी मैच के बीच से हट गई. दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी आयुष ने इस सुपर 1000 टूर्नामेंट के पहले दौर में दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी चीन के होंग येंग चेंग को 8-21, 22-20, 21-15 से हराया. पहले गेम में करारी हार के बाद 21 साल के आयुष ने दूसरे गेम में 11-15 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मुकाबले को तीसरे और निर्णायक गेम में खींचा. बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता आयुष ने तीसरे और निर्णायक गेम में पूरी तरह से दबदबा बनाते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया जहां उनकी भिड़ंत हांगकांग के ली च्युक यू से होगी. सात्विक और चिराग को हालांकि पुरुष एकल के पहले दौर के मुकाबले से सात मिनट में ही हटना पड़ा. भारतीय जोड़ी को सात्विक के कंधे में चोट के कारण मुकाबले से हटना पड़ा. भारतीय जोड़ी जब केंग खाइ शिंग और आरोन टाइ की मलेशिया की जोड़ी के खिलाफ 6-11 से पीछे थी तब सात्विक को अपने दाएं कंधे की ओर इशारा करते देखा गया और इसके बाद इस सुपर 1000 टूर्नामेंट के पहले दौर के मुकाबले को रोक दिया गया. पिछले हफ्ते भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन जीतकर दो साल में अपना पहला खिताब जीता था. पुरुष एकल में एचएस प्रणय को पहले दौर में ही आयरलैंड के एनहाट एनगुएन के खिलाफ तीन गेम में शिकस्त झेलनी पड़ी. पहले गेम 17-21 से गंवाने के बाद प्रणय ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-16 से जीता लेकिन तीसरे और निर्णायक गेम में 19-21 की हार के साथ मुकाबला गंवा दिया. मिश्रित युगल में रोहन कपूर और रुतविका गड्डे की दुनिया की 41वें नंबर की भारतीय जोड़ी ने पो सुआन येंग और लिंग फेंग हू की चीनी ताइपे की जोड़ी के खिलाफ 21-14, 21-14 की जीत से दूसरे दौर में जगह बनाई.

सिराज और प्रसिद्ध ने भीषण गर्मी में भी किया जमकर अभ्यास

मुल्लांपुर: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के खिलाफ छह जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले बुधवार को यहां भीषण गर्मी के बावजूद लगभग 25 मिनट तक जमकर अभ्यास किया. इस एकमात्र टेस्ट मैच के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैच की वनडे श्रृंखला खेली जाएगी. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दो महीने तक व्यस्त रहने के बाद गेंदबाजों के कार्यभार को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे, लेकिन चिलचिलाती धूप में सिराज की शानदार गेंदबाजी से स्पष्ट हो गया कि इस सीनियर तेज गेंदबाज की फिटनेस को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं है. अगर सिराज फिट नहीं होते तो उनके लिए चिलचिलाती धूप में अपनी पूरी ताकत से गेंदबाजी करना आसान नहीं होता. लेकिन उनकी गेंदबाजी को देखकर लगता है कि वह इस टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. अभ्यास सत्र के दौरान छह फुट पांच इंच लंबे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अच्छी लेंथ से तेज उछाल हासिल की. कम से कम दो मौकों पर उनकी गेंद केएल राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पीछे गई. राहुल इसके अलावा अभ्यास के दौरान तकनीकी रूप से काफी कुशल नजर आए. जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी डार ने कई चरणों में गेंदबाजी की.

इंग्लैंड ने भारत को तीसरे टी 20 में 6 विकेट से हराया, श्रृंखला 2-1 से जीती

टॉनटन: एलिस कैप्सी और हीदर नाइट की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार देर रात (भारतीय समयानुसार बुधवार) को भारत को अंतिम टी20 मुकाबले में 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली. 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी की और 18.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही. दूसरे ही ओवर में डैनी वायट-हॉज आउट हो गईं, जबकि सोफिया डंकली भी जल्दी पवेलियन लौट गईं. पावरप्ले के अंतिम ओवर में एमी जोन्स का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड दबाव में दिख रहा था. हालांकि इसके बाद एलिस कैप्सी ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार हमला बोला और केवल 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. दूसरी ओर कप्तान हीदर नाइट ने संयम के साथ पारी को संभाला और धीरे-धीरे रन गति बढ़ाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी ने भारत की वापसी की उम्मीदों को खत्म कर दिया. कैप्सी ने 82 रन की शानदार पारी खेली, जबकि नाइट 70 रन बनाकर नाबाद लौटीं. अंत में नाइट ने चौके के साथ इंग्लैंड को जीत दिलाई. इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 180 रन बनाए. भारतीय टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो गईं. इसके बाद यास्तिका भाटिया ने तेज बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में रन गति बनाए रखी. उन्होंने आकर्षक शॉट्स लगाए लेकिन रन आउट होकर पवेलियन लौट गईं. मध्यक्रम में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी संभाली और नाबाद 56 रन बनाए. हालांकि अंतिम पांच ओवरों में भारतीय टीम केवल 48 रन ही जोड़ सकी, जो अंत में निर्णायक साबित हुआ. इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल ने महत्वपूर्ण दो विकेट लिए.

कारोबार

इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन पर बड़ा दांव

39,290 करोड़ रुपये की छह बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी

मुंबई : बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने देश के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने और विमानन क्षेत्र को वित्तीय झटकों से बचाने के लिए कुल 39,290 करोड़ रुपये के छह अहम प्रोजेक्ट्स को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इन नीतिगत फैसलों का सीधा असर देश की एविएशन इंडस्ट्री की बैलेंस शीट, कमर्शियल परिवहन व्यवस्था और राज्यों की इंटर-सिटी कनेक्टिविटी पर पड़ेगा. इस मेगा पैकेज में विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए एक विशेष फंड बनाने के साथ-साथ दिल्ली के प्रदूषण स्तर को कम करने और चार प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को रफ्तार देने पर रणनीतिक फोकस किया गया है. कैबिनेट के मौजूदा फैसलों में कुल स्वीकृत बजट का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर विमानन क्षेत्र की स्थिरता और राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरण सुधार के लिए रखा गया है. ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाले भारी उतार-चढ़ाव से घरेलू विमानन कंपनियों को बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का 'एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड' स्थापित करने का अहम फैसला किया गया है. एविएशन इंडस्ट्री लंबे समय से ईंधन की अस्थिर लागत से जूझ रही थी. यह फंड एयरलाइंस की परिचालन लागत को स्थिर रखने और मार्जिन को सुरक्षित करने में मददगार साबित

होगा. पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतें मार्च 2026 में 60.5 रुपये से बढ़कर मई 2026 में 142 रुपये प्रति लीटर हो गईं. एटीएफ एयरलाइंस की परिचालन लागत का 40 फीसदी है, जिससे एयरलाइंस और तेल विपणन कंपनियां प्रभावित हुईं. इस स्थिति से निपटने के लिए कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये के एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी है. सरकार ने घरेलू परिचालन के लिए एटीएफ की कीमत 75.6 रुपये प्रति लीटर तय की है. यह आत्मनिर्भर कोष घरेलू व अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए उपलब्ध रहेगा. यह भारतीय विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ कीमतें स्थिर करेगा. इससे हवाई यात्रियों को किराए में वृद्धि से बचाया जा सकेगा और 77 लाख नौकरियों की रक्षा होगी. यह विमानन परिचालन को व्यवहार्य बनाए रखकर सार्वजनिक निवेश व कनेक्टिविटी को सुरक्षित रखेगा. राजधानी दिल्ली में बढ़ते एमिशन (उत्सर्जन) और वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए एक विशेष योजना पेश की गई है. इसके तहत पुराने ट्रकों और बसों को सड़कों से हटाने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसके लिए 5,041 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. देश में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को विश्वस्तरीय बनाने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने कुल 39,290 करोड़ रुपये के इस पैकेज में से 24,249 करोड़ रुपये (कुल राशि का लगभग 62 प्रतिशत) केवल नई सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आवंटित किए हैं. इन परियोजनाओं से ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और बिहार में माल ढुलाई और व्यापारिक परिवहन अधिक सुगम होगा.

ओडिशा (कोस्टल हाईवे): पूर्वी तट पर कनेक्टिविटी बेहतर करने और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रामेश्वर, कोणार्क और पारादीप को जोड़ने वाले कोस्टल हाईवे के निर्माण को हरी झंडी दी गई है. इसके लिए 8,301 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

तेलंगाना (फोर-लेनिंग प्रोजेक्ट): दक्षिण भारत में औद्योगिक परिवहन को तेज करने के लिए तेलंगाना में एनएच-63 और एनएच-563 के विभिन्न हिस्सों को चार लेन का बनाने का फैसला हुआ है. इस परियोजना के लिए 7,597 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

मध्य प्रदेश (राजमार्ग अपग्रेडेशन): मध्य भारत में सड़क नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए एनएच-347इ के आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए 4,415 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति मिली है.

बिहार (सड़क विस्तार): राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के तहत खगड़िया से पूर्णिया तक एनएच-31 और एनएच-231 के सेक्शन को चार लेन में बदलने के लिए 3,936 करोड़ रुपये पास किए गए हैं.

आर्थिक प्रभाव और आगे की राह : कैबिनेट के इन छह प्रमुख फैसलों का समग्र विश्लेषण यह दर्शाता है कि सरकार का मुख्य फोकस लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने, सुरक्षित व तेज यातायात सुनिश्चित करने और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कम करने पर है. 10,000 करोड़ रुपये के 'एटीएफ स्टेबलाइजेशन फंड' से जहां एक ओर एयरलाइंस को ईंधन के मोर्चे पर अप्रत्याशित वित्तीय झटकों से राहत मिलेगी, वहीं 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित राज्यों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. कुल मिलाकर, यह 39,290 करोड़ रुपये का आवंटन भारत की विकास गाथा और घरेलू आपूर्ति शृंखला को एक मजबूत गति प्रदान करेगा.

लोन डिफॉल्टरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

समझौते के बाद नहीं चलाया जा सकता क्रिमिनल केस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर बैंक और कर्जदार लोन खाते के निपटारे के लिए समझौता कर लेते हैं तो उसके बाद लोन डिफॉल्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती. अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसी कार्यवाही को अनुमति देना न केवल दमनकारी होगा बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेगा. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने एक बिजनेसमैन की याचिका स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद कर दिया. बेंच ने कहा कि बैंकिंग लेन-देन मूल रूप से व्यावसायिक मामला होता है. जब दोनों पक्ष आपसी समझौते से विवाद सुलझा लेते हैं तो बाद में आपराधिक केस चलाना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है. इस मामल में बिजनेसमैन ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के सामने बैंक के साथ समझौता किया था. जिसमें 6.49 करोड़ रुपये के बकाया के मुकाबले 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया. जिसमें 3.09 करोड़ ब्याज की राशी थी. समझौते के दो साल बाद बैंक ने धोखाधड़ी और जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज कराया. उइख ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिजनेसमैन ने ऑडिट रिपोर्ट की जाली कॉपियों से कैश क्रेडिट लिमिट बढ़वाई थी. अदालत ने कहा, दोनों पक्षों के बीच विवाद खत्म हो चुका है. ऐसे में आरोपी के दोषी ठहराए जाने की संभावना न के बराबर है. केस जारी रखना अन्याय होगा. बेंच ने आगे कहा कि यदि डीआरटी के सामने हुए समझौते के बाद भी आपराधिक कार्रवाई चलाने की इजाजत दी गई तो निपटारे का क्या ? इससे व्यावसायिक संस्थाएं और उद्यमी बैंकिंग विवादों के समाधान से हिचकिचाएंगे, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

रिकवरी की कोशिशों के बाद भी लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 304 अंक टूटा

मुंबई : बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक नुकसान के साथ बंद हुए. आईटी शेयरों में भारी बिकवाली इसका मुख्य कारण रही. कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने भी बाजार को प्रभावित किया. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 303.67 अंक या 0.41 फीसदी गिरकर 74,346.17 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 1,157.24 अंक या 1.55 फीसदी तक गिरकर 73,492.60 पर पहुंच गया था. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 77.95 अंक या 0.33 फीसदी की गिरावट के साथ 23,405.60 पर बंद हुआ. इससे पहले मंगलवार को बाजार में चार दिन की गिरावट का सिलसिला टूटा था. उस दिन सेंसेक्स 382.50 अंक और निफ्टी 100.95 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स की तीस कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 8.43 फीसदी गिरी. टेक महिंद्रा 6.23

फीसदी, एचसीएल टेक 5.25 फीसदी और इंफोसिस 3.82 फीसदी नीचे आए. आईटीसी, एटर्नल, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज फाइनेंस भी नुकसान में रहे. इंटरग्लोब एविएशन, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और ट्रेंट लाभ में रहे. वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड तीन फीसदी उछल गया. यह 98.92 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 8,362.92 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. यह जानकारी एक्सचेंज के आंकड़ों से मिली है.

न्यूज़ कॉर्नर

ईडी की घी व्यापारी के ठिकानों पर अचानक छापेमारी, हड़कंप

बीकानेर: आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद से जुड़े मामले में लगातार कार्रवाई जारी है. इसी क्रम में बीकानेर में बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पहुंची. यहां टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ईडी के अधिकारियों ने शहर की प्रसिद्ध 'कोयला गली' स्थित नामचीन घी व्यापारी 'मोहनलाल आशीष कुमार अग्रवाल' के ठिकानों पर अचानक छापेमारी की. सुबह-सुबह हुई इस बड़ी रेड से प्रदेश के पूरे व्यापारिक जगत और शहर में हड़कंप मच गया. मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद (लड्डू) से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर की गई. आरोप है कि बीकानेर की इस संबंधित फर्म ने तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए घी की सप्लाई की थी. पिछले दिनों तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर देशव्यापी विवाद खड़ा हुआ था, और आशंका जताई जा रही है कि इसी मामले में वित्तीय गड़बड़ियों और सप्लाई चैन की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी ने यहां दस्तक दी है. ईडी के अधिकारी व्यापारी के दफ्तर और अन्य ठिकानों पर दस्तावेजों, कंप्यूटर हार्डडिस्क और बैंक खातों की गहनता से छानबीन कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह जब ईडी की टीम कोयला गली स्थित व्यापारी के प्रतिष्ठान पर पहुंची, तो केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूरे परिसर को अपने घेरे में ले लिया.

दिल्ली होटल दुखांतिका: अजमेर व किशनगढ़ के तीन जनों की हुई मौत

अजमेर: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी भीषण अग्निकांड में किशनगढ़ के लक्ष्मीनारायण कॉलोनी निवासी अशोक पंसारी, गुलाब बाड़ी अजमेर निवासी यूको बैंक से सेवानिवृत्त जवंरीलाल अग्रवाल व उनकी पत्नी कमला अग्रवाल की मौत हो गई. सूचना मिलने पर अजमेर व किशनगढ़ में दुख व शोक व्याप्त हो गया. समाजबंधु इस घटना से बेहद आहत हैं. बताते हैं एक जून को कमला अग्रवाल का जन्म दिन मनाया गया था जिसे आस पड़ोस के लोगों ने मनाया था. बताया जा रहा है कि अग्रवाल दम्पती के शव गुरुवार को अजमेर लाए जाएंगे. अजमेर पुलिस अधीक्षक ने मामले में संवेदनशीलता दर्शाते हुए परिवारजनों से सम्पर्क कर व्यवस्थाओं में यथा संभव सहयोग का आश्वासन दिया है. पड़ौसी भगवती गुप्ता ने बताया जवंरीलाल व कमला अग्रवाल दोनों ही बेहद सामाजिक थे. व्यवहार से काफी कुशल थे. लायंस क्लब और भारत विकास परिषद, अग्रवाल समाज आदि संस्थाओं से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए थे. बताते हैं कि इनके पुत्र गूगल में अमेरिका काम करते हैं और पुत्री जयपुर में ब्याही हुई है. पड़ौसियों ने बताया कि वे दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती फूफाजी राधेश्याम अग्रवाल का हालचाल जानने गए थे. दिल्ली मेंदेर रात को सभी लोग होटल में रुके हुए थे. होटल में आज सुबह भीषण आग ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया. इस दर्दनाक हादसे में अशोक पंसारी, उनकी छोटी बुआ अजमेर गुलाब बाड़ी निवासी कमला देवी और उनके पति जंवरीलाल की मौत हो गई.

नूंह में दर्दनाक सड़क हादसा, एक होमगार्ड जवान की मौत, दो घायल

नूंह: नूंह जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जबकि दो अन्य जवान घायल हो गए. यह हादसा दिल्ली-अलवर रोड पर बॉडी कोठी के पास उस समय हुआ, जब नूंह पुलिस लाइन से ड्यूटी पूरी कर तीनों होमगार्ड जवान फिरोजपुर झिरका लौट रहे थे.मृतक की पहचान राजकुमार निवासी गांव रावली के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है. राजकुमार स्वयं कार चला रहा था. कार में उसके साथ होमगार्ड जवान आरिफ और महेश भी सवार थे.बताया जा रहा है कि तीनों जवान मंगलवार की रात नूंह पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज कराने के बाद कार से फिरोजपुर झिरका की ओर जा रहे थे. इसी दौरान बॉडी कोठी के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी पुलिया से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरिफ और महेश घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मांडी खेड़ा अस्पताल भिजवा दिया गया.

पत्नी की हत्या कर शव बाइक पर ले जाकर झाड़ियों में फेंका, पति गिरफ्तार

रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले के गांव धवाना की बणी में झाड़ियों से महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने बुधवार को उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी की हत्या के बाद शव को बाइक पर ले जाकर जंगल में फेंक दिया था.पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 26 वर्षीय ज्योति कुमारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गांव कुमीडीया की रहने वाली थी. वह वर्तमान में अपने पति कंवरपाल के साथ रेवाड़ी के गांव मंदोला में रह रही थी. दोनों की शादी वर्ष 2018 में हुई थी और उनका एक चार वर्षीय बेटा भी है. मृतका के पिता राम आधार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कंवरपाल नशा करने का आदी था और अक्सर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था. 30 मई को उन्होंने बेटी को फोन कियाए लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की. अगले दिन भी संपर्क नहीं हो पाया और बाद में मोबाइल बंद मिला. इसके बाद उन्होंने थाना खोल पुलिस को शिकायत दी. जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें 31 मई को झाड़ियों में मिले एक महिला के शव की जानकारी दी, जिसकी पहचान ज्योति कुमारी के रूप में हुई. पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी.

नशीली गोलियां रखने के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

जींद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने नशीली गोलियां रखने के दोषी को बुधवार को 10 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार दस अगस्त 2019 को पुलिस को सूचना मिली थी कि शर्मा नगर भिवानी रोड निवासी सुनील ने किराये पर दुकान ली हुई है. जिसमें वह बच्चों को वीडियो गेम खिलाता है. उसी दुकान की आड़ में वह नशीली दवाइयों का कारोबार भी करता है. सूचना के आधार पर पुलिस ने सुनील पर निगाह रखनी शुरु कर दी. सुनील नशीली दवाइयों को पॉलीथिन में डाल दुकान की तरफ जा रहा था तो उसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उसे काबू कर लिया. तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से 120 गोली (कुल वजन 27 ग्राम 48 मिलीग्राम) प्रतिबंद्धित एल्प्राजोलम बरामद हुई थी. शहर थाना पुलिस ने सुनील के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था. बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने नशीली गोलियां रखने के दोषी सुनील को 10 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जींद पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

बड़े भाई की हत्या के दोषी छोटे भाई को उम्र कैद की सजा

जींद: जिला सत्र एवं न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने बड़े भाई की हत्या के मामले में छोटे भाई को दोषी करार देते हुए बुधवार को उम्र कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव लोधर निवासी संदीप की पत्नी ममता ने 18 मई 2024 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि संदीप तथा उसका भाई सुनील खेत में मकान बना कर रहे थे. दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई. शराब के नशे मे धुत्त सुनील ने अपने बड़े भाई संदीप पर लाठी तथा तेजधार हथियार से हमला कर दिया. जिसमें संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया. संदीप के परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. संदीप को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया. उचाना थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया था. पुलिस ने बड़े भाई की हत्या करने पर मृतक की पत्नी ममता की शिकायत पर छोटे भाई सुनील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था. बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा कि अदालत ने सुनील को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.

गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन

पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास मिले आधार कार्ड, पुलिस कर रही जांच

अहमदाबाद : अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शहरव्यापी अभियान में कई संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिए है. इसके साथ ही इन प्रवासियों के बारे में सबूत जुटाए हैं. उन्होंने धोखाधड़ी के माध्यम से आधार कार्ड लिए थे. इसके चलते दस्तावेज जालसाजी नेटवर्क और भारत में उनके रहने को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों की व्यापक जांच शुरू की गई है.

बुधवार को चल रही कार्रवाई पर जानकारी देते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), शरद सिंघल ने कहा कि गुजरात भर में चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान 'ऑपरेशन डेल्टा हंट' के दौरान गिरफ्तार किए गए 300 से अधिक व्यक्तियों में से अब तक 166 लोगों की बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पुष्टि की गई है. सिंघल ने कहा, इन 166 लोगों में से काफी लोगों ने अवैध रूप से भारतीय आधार कार्ड बनवाए थे. हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये दस्तावेज किसके माध्यम से बनवाए गए थे.' उन्होंने आगे बताया कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये लोग भारत में कैसे दाखिल हुए. वह क्या काम करते

थे और वह किन माध्यमों से पैसे भेजते थे. अहमदाबाद में यह अभियान शहर के पुलिस आयुक्त जीएस मलिक की देखरेख में चलाया गया. इसमें क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और स्थानीय पुलिस स्टेशनों से ली गई 30 से अधिक टीमें शामिल थीं. नारोदा, दानिलिमदा, वटवा, वटवा जीआईडीसी, जुहापुरा और अन्य क्षेत्रों में छापेमारी और सत्यापन अभियान चलाए गए. सिंघल ने कहा कि मानवीय स्रोतों और तकनीकी निगरानी दोनों के माध्यम से जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चलता है कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग चंदोला झील के आसपास पहले की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों से जुड़े हो सकते हैं.

उन्होंने कहा, पिछले साल जब हमने चंदोला ऑपरेशन चलाया था, तब कई लोग भाग गए थे. मिली जानकारी के अनुसार, उनमें से कुछ लोग बाद में अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में रहने लगे थे. पुलिस ने इस अभियान के दौरान 300 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हिरासत में लिया. यह ताजा अभियान पिछले साल अहमदाबाद में चलाए गए एक बड़े अभियान के बाद शुरू किया गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने 465 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित कर दिया था. सिंघल ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. जांचकर्ता इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि कथित तौर पर जाली भारतीय पहचान दस्तावेज कैसे प्राप्त किए गए, और यह जांच अवैध आप्रवासन से आगे बढ़कर राज्य के भीतर संचालित दस्तावेज धोखाधड़ी नेटवर्क को सक्षम बनाने के संदिग्धों तक भी पहुंचने की उम्मीद है.

नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष लामिछाने ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की

नई दिल्ली: नेपाल के सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बुधवार को मुलाकात की. दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि, विकास और क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की.प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते कहा कि रबि लामिछाने से मिलकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और साझा तथा समृद्ध भविष्य के निर्माण की इच्छा का वह पूरा समर्थन करते हैं. भारत के लिए नेपाल उसकी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक साझेदार है.प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल भारत का प्राथमिक साझेदार है और नई सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के विशेष और बहुआयामी संबंधों को और ऊंचाई तक ले जाने की इच्छा है. भारत और नेपाल के बीच संबंध ऐतिहासिक और बहुआयामी हैं. दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव गहरे हैं.प्रधानमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर साझा भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. दोनों देशों के बीच सहयोग से क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को नई दिशा मिलेगी. उल्लेखनीय है कि लामिछाने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 01 से 05 जून तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं. उन्होंने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से केंद्रीय मुख्यालय में मुलाकात की थी. भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया था.

कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला

एक भारतीय की मौत; इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है. कुवैत में भारतीय दूतावास ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते

सैन्य तनाव के बीच बुधवार को कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया. घटना के बाद भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कुवैत आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानें 4 जून 2026 को दोपहर 12 बजे तक निलंबित कर दी हैं. जानकारी के अनुसार, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 यात्री भवन को ड्रोन ने निशाना बनाया. हमले के बाद कुवैती नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से देश का एयरस्पेस बंद करने का फैसला लिया.

कुवैत सिविल एविएशन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सभी हवाई यातायात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है और उड़ानों को वैकल्पिक हवाई अड्डों की ओर डायवर्ट किया जा रहा है. इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है. एयरलाइन ने कहा, हम समझते हैं कि इससे यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित होंगी और इसके लिए हमें खेद है, लेकिन हमारे ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.एयरलाइन ने बताया कि वह क्षेत्रीय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और संबंधित विमानन प्राधिकरणों के संपर्क में है. सुरक्षित परिस्थितियां बनने और संचालन के लिए सुरक्षित हवाई मार्ग उपलब्ध होने पर सेवाएं फिर शुरू की जाएंगी. इंडिगो ने यात्रियों से एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांचने की अपील की है. प्रभावित यात्रियों को रीबुकिंग या फुल रिफंड का विकल्प भी दिया गया है.

तीन हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 नामों की अनुशंसा की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय में जज के रुप में नियुक्त करने के लिए 10 नामों की अनुशंसा की है. कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो एडिशनल जजों को स्थायी जज के रुप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है. कॉलेजियम की 02 जून को हुई बैठक में इस आशय की सिफारिश की गई.कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए 06, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए 01 और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए 03 जजों को नियुक्त करने की सिफारिश की है. कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज के रुप में जिन नामों की अनुशंसा की है उनमें राघवेंद्र सीताराम श्रीवास्तव, हेमा कुलकर्णी, एस रंगाराव, टीपी विवेकानंद, बी प्रमोद और एचजीएस भूषण शामिल हैं.कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जज के रुप में नियुक्त करने के लिए वकील अमित लाहोटी के नाम की अनुशंसा की है. इसी तरह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जज के रुप में जिन नामों की अनुशंसा की गई है उनमें चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल शामिल हैं. कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एडिशनल जजों जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नालवा को स्थायी जज के रुप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है.

नासिक टीसीएस मामला : आरोपपत्र में एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का भी नाम शामिल

नासिक: टीसीएस के नासिक कार्यालय से जुड़े यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. नासिक पुलिस द्वारा दाखिल पहले आरोपपत्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का नाम सीधे तौर पर शामिल होने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज इस पहले मामले में बलात्कार, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं. लगभग 3,500 पन्नों का यह पहला आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया है.

मुख्य आरोपित निदा खान को अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वह फरार हो गई थी. तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. जांच के दौरान एआईएमआईएम के पूर्व नगरसेवक मतीन पटेल द्वारा उसे छिपाने में मदद करने की बात सामने आई. पूछताछ के दौरान मतीन पटेल ने कथित रूप से कहा की इसके लिए इम्तियाज जलील साहब से पूछना होगा. इसके बाद पुलिस ने नारेगांव-कौसर सिडको इलाके में छापा मारकर निदा खान और उसके परिवार को हिरासत में लिया. जिस घर में निदा खान छिपी हुई थी, उस सहित दो अन्य संपत्तियों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. इस मामले में घर के मालिक हनीफ खान को भी सह-आरोपित बनाया गया है.

फिलहाल, हज यात्रा के लिए सऊदी अरब में मौजूद इम्तियाज जलील ने फोन पर प्रतिक्रिया देता हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम आरोपपत्र में शामिल किया गया है. मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं. जलील ने यह भी स्वीकार किया कि वह पीड़ित परिवार से मिले थे.

पानीपत: हाई वोल्टेज तारों से ट्रक में लगी आग, लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख

पानीपत: नूरवाला स्थित गैस गोदाम के पास बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां विदेशों से आयात किए गए वेस्ट कपड़ों से लदा एक ओवरलोड ट्रक जैसे ही गैस गोदाम वाली गली में मुड़ा तो ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्टेज की हाईटेंशन तारों को छू गया. तारों से छूते ही ट्रक में लदे कपड़ों में भयंकर आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में ट्रक का टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया.

जानकारी के अनुसार, ट्रक में लदा वेस्ट कपड़ा विदेश से विशेष रूप से आयात कर पानीपत लाया जाता. इसी दौरान इस माल को पानीपत के

नूरवाला कुटानी रोड स्थित एक गोदाम में पहुंचाया जा रहा था. जैसे ही ट्रक गैस गोदाम वाली गली में पहुंचा, तो ट्रक की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वह गली के ऊपर से जा रही 11 हजार वोल्टेज की हाईटेंशन तारों से छू गया जिस कारण तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण वेस्ट कपड़े ने तुरंत आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा. इसी बीच आग की चपेट में आने से ट्रक का टायर भी जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाके की आवाज सुनकर लोगों की कुछ समझ नहीं आया, ओर वे घबराकर इधर-उधर भागने लगे. हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया. फायर ब्रिगेड कर्मचारीयों ने आग की विकरालता को देखते हुए पानी की सामान्य गाड़ियों के साथ-साथ फॉम टेंडर की गाड़ियों को भी मौके पर बुला लिया. फायर विभाग की करीब 10 गाड़ियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस आगजनी में करीब 15 लाख रुपए का कीमत का विदेशी माल जल कर राख हो गया और ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

तिरुपति के प्रसादम् घी मिलावट मामले में ईडी की देश के 15 स्थानों पर छापेमारी, 60 लाख नकद और 45 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के प्रसादम् में घी मिलावट घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को देशभर के 15 जगहों पर छापेमारी की. यह छापेमारी आहिल्यानगर (महाराष्ट्र), बीकानेर (राजस्थान), देहरादून (उत्तराखंड), दिल्ली, डिंडीगुल (तमिलनाडु), गुंटूर (आंध्र प्रदेश), मुंबई (महाराष्ट्र) और रुड़की (उत्तराखंड) में की गई. इस दौरान 60 लाख रुपये नकद बरामद किए गए और 45 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों में अपराध की आय निवेश किए जाने का खुलासा हुआ.

ईडी की तरफ से बताया गया कि तलाशी में आरोपित पोमिल जैन, विपिन जैन, राजू राजशेखरन, राजेश मंसुखलाल छावड़ा, अपूर्व विनयकंठ छावड़ा, मचींद्र शंकरराव लंके, अजय कुमार सुगंध, महेश कुमार रोहिरा और आशीष अग्रवाल के आवासीय व कार्यालय परिसरों को खंगाला गया. इसके अलावा एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड (डिंडीगुल, तमिलनाडु), मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आहिल्यानगर, महाराष्ट्र) और भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड (रुड़की, उत्तराखंड) के डेयरी संयंत्रों पर भी छापेमारी की गई. यहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिनसे पता चला कि अपराध की आय को छिपाने के लिए जटिल कानूनी संस्थाओं का नेटवर्क इस्तेमाल किया गया.जांच में सामने आया कि आरोपितों ने कुछ टीटीडी अधिकारियों के साथ मिलकर मिलावटी घी की आपूर्ति की और धोखाधड़ी कर ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाया. अपराध की आय को बाद में विभिन्न अचल संपत्तियों में निवेश किया गया. ईडी ने कहा कि आगे की जांच जारी है.

सुडोकू–66

1	6	9	3		2			
2	7			1			9	
5		3		6	4	1		
4	5	2						1
			5		1			
8						9	5	3
		8	7	3		4		5
	3			4			7	2
			2		6	8	3	9

9X9 के उपरोक्त खानों में एक से नौ तक के अंक ऐसे भरें ताकि हर कॉलम और उसके हर छोटे खाने में एक नंबर ही आयें.

उत्तर अगले अंक में

सूडोकू -65 का उत्तर

6	3	1	8	2	7	9	5	4
9	7	5	3	4	1	6	2	8
2	8	4	9	6	5	1	3	7
1	9	3	2	7	8	5	4	6
7	2	6	4	5	3	8	1	9
5	4	8	1	9	6	3	7	2
3	5	9	7	8	2	4	6	1
8	1	7	6	3	4	2	9	5
4	6	2	5	1	9	7	8	3

युवा शक्ति माथापच्ची- 87

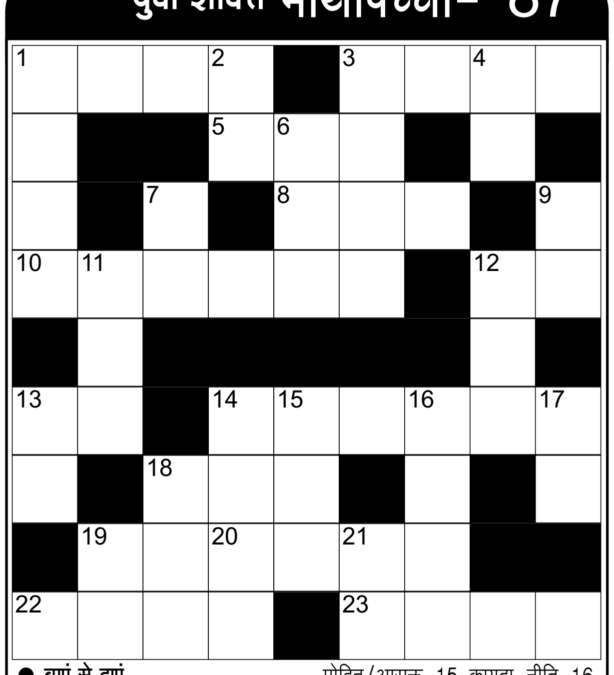

● **बाएं से दाएं**

1. अनिष्ट, अहित, अनादर, 3. व्यंजन, घी में तलकर बनाया हुआ खाद्य पदार्थ, 5. लौटाया हुआ, लौटाना, 8. धवल, चांदी, 10. धैर्य, रखना, 12. देवराज, देवेन्द्र, 13. विभिन्न, 14. अव्यवस्थित, नियम विरुद्धता, 18. न्याय का उलटा, 20. बुद्धि, अक्ल, 22. गहरा लाल, इन्फ्रारेड, 23. गिरना, बूंद-बूंद कर निकलना,

● **उपर से नीचे**

1. दोषी, पापी, 2. कण, सूजी, 3. दया आना, पसीने से तर होना, 4. पवन, हवा, 6. जांच, 7. जिससे छाना जाता है, सूप, 9. सभ्य, साधु, बैल, चंदन, 11. निवास करना, बसना, 12. इशारा, संकेत, 13. संज्ञा, आख्या, 14. दूसरे पर मोहित/आसक्त, 15. कायदा, नीति, 16. प्राप्त, 17. कपड़े की बुनाई में लम्बाई-चौड़ाई में लगा धागा, 19. चित्त, मन, दर, 21. एकदम, तत्काल, फौरन,

उत्तर कल के अंक में

माथापच्ची- 86 का हल

	आ	न		आ	प	स		नि
	प	र	मा	त्मा		प्र	ति	ष्ठा
आ	दा	ब			द	मा		पू
		लि			बा	ण		र्व
अ	न्न		त	ना	व		ढा	क
नु		आ	म			प		
सं		य	क			धा	म	न
धा	र	क		उ	ता	र	ना	
न		र	का	ब		ना	ना	

सरकारी कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे तो अनुपस्थित माने जाएंगे

बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी अनिवार्य

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति और समयपालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है. नवान्न की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना और समय पूरा होने तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा और अवकाश भी काटा जा सकता है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, समयपालन सुनिश्चित करने, कार्यालयों में अनुशासन स्थापित करने और उपस्थिति रिकॉर्ड के डिजिटल संरक्षण के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है. यह नई व्यवस्था नवान्न स्थित सभी विभागों में 15 जून से लागू होगी, जबकि 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में इसे लागू कर दिया जाएगा. मंगलवार को राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने भी कहा था कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने काम के प्रति जवाबदेह होना होगा. उन्हें समय पर कार्यालय आना और समय पर ही कार्यालय छोड़ना होगा. सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी.

अधिसूचना की प्रमुख बातें :- पश्चिम बंगाल सेवा नियमावली (भाग-1) के नियम 29ए के तहत कर्मचारियों को मुख्यालय से 8 किलोमीटर के भीतर निवास करने की अनिवार्यता से जो छूट पहले से प्राप्त है, वह जारी रहेगी. नवान्न में कार्यरत सभी कर्मचारियों (विभागाध्यक्षों को छोड़कर) के लिए कार्यालय में प्रवेश और निकास का समय चेहरा पहचान पर आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज करना अनिवार्य होगा. सुबह 10:15 बजे से 11:00 बजे के बीच उपस्थिति दर्ज कराने पर कर्मचारी को विलंब से उपस्थित माना जाएगा. सुबह 11:00 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज कराने पर कर्मचारी को उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा. शाम 5:15 बजे से पहले कार्यालय छोड़ने पर इसे निर्धारित समय से पूर्व प्रस्थान माना जाएगा. यदि कोई कर्मचारी एक ही दिन देर से पहुंचे और निर्धारित समय से पहले कार्यालय छोड़ दे, तो उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा तथा उसका एक दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा. कार्यालय छोड़ते समय बायोमेट्रिक प्रणाली में आउट-पंच नहीं करने पर भी कर्मचारी को अनुपस्थित माना जाएगा. किसी महीने में तीन बार देर से पहुंचने या समय से पहले कार्यालय छोड़ने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश अथवा बाल देखभाल अवकाश काटा जाएगा. पश्चिम बंगाल सेवा नियमावली (भाग-1) के नियम 15 के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों को कार्यालय समय समाप्त होने के बाद भी सरकारी कार्य करना होगा. यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को आधिकारिक बैठक अथवा सरकारी कार्य के कारण देर से आना या पहले जाना पड़े, तो संबंधित विभागाध्यक्ष आवश्यक अनुमोदन की व्यवस्था करेंगे. सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने और सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी अधिक प्रभावी होगी और सरकारी सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी.

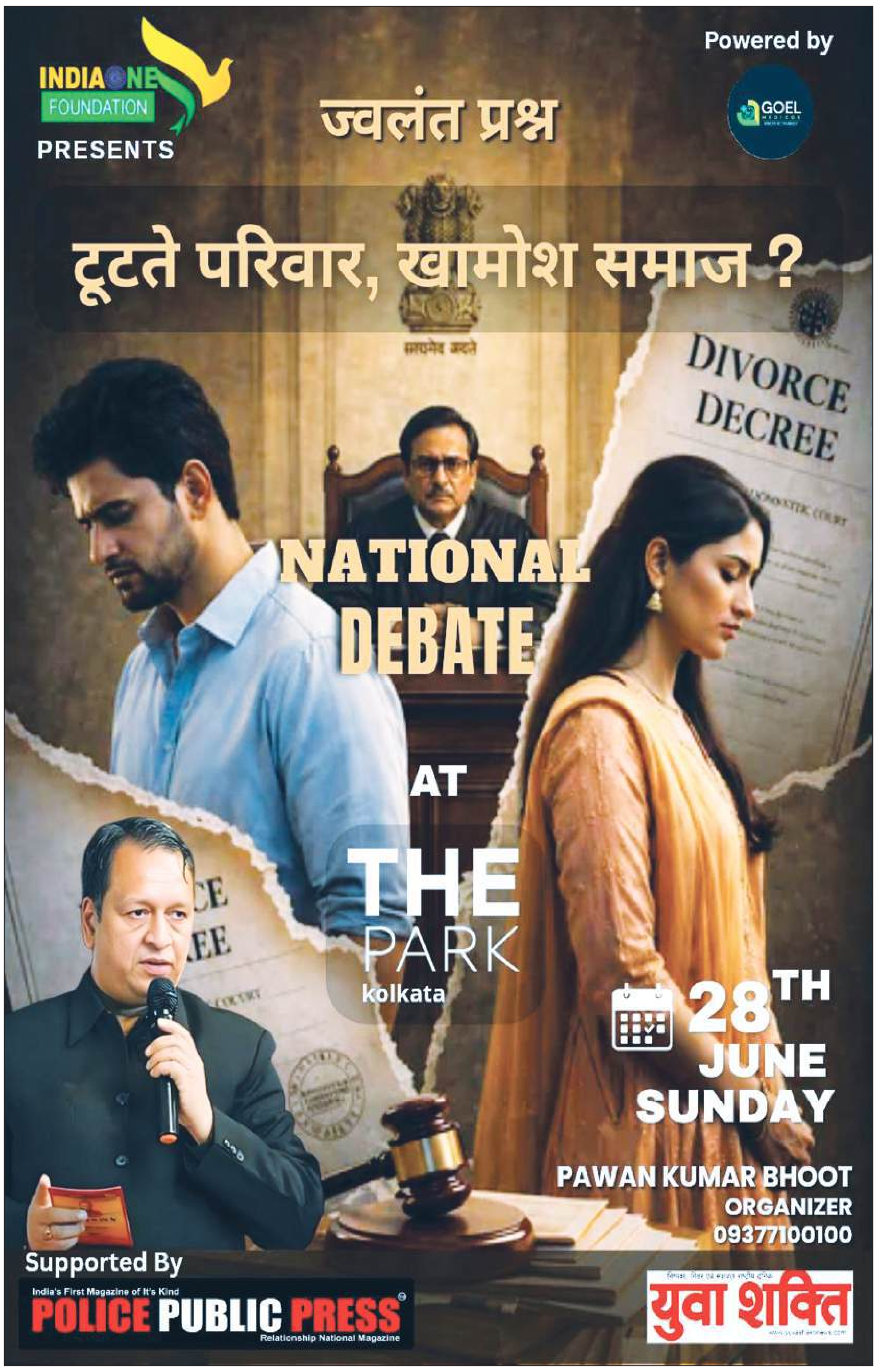

कोलकाता नगर निगम की मासिक बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को : हाई कोर्ट

कोलकाताः कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि कोलकाता नगर निगम की अध्यक्ष माला राय नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मासिक बैठक बुला सकती हैं. कोर्ट के इस आदेश को राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर चल रही अटकलों के बीच अहम माना जा रहा है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि नगर निगम की अध्यक्ष को कानून के तहत मासिक बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त है. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि 22 मई को आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों की प्रति शपथपत्र के रूप में 9 जून तक कोर्ट में जमा कराई जाए. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी. यह मामला तब अदालत पहुंचा था जब आरोप लगाया गया कि अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाए जाने के बावजूद नगर निगम की नियमित मासिक बैठक आयोजित नहीं हो सकी. इसके बाद इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. गौरतलब है कि, राज्य में सरकार बदलने के बाद कोलकाता नगर निगम को भंग किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं.

ममता के धरने पर दिलीप घोष का कटाक्ष, कहा- उनके साथ कोई नहीं

कोलकाता : राज्य के पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के धरने पर कटाक्ष किया है. बुधवार सुबह पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने कहा, यह कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था. यह जबरदस्ती कराया गया कार्यक्रम था. पार्टी के सांसद और विविधायक भी इसमें शामिल नहीं हुए. केवल वही लोग वहां मौजूद थे, जिनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी और जो विशेष लाभ पाने वाले हैं. उनके (ममता) साथ कोई नहीं है. दिलीप घोष ने आगे कहा, जो लोग कभी हमारे नेताओं के नाम लेकर गालियां दिया करते थे, वही अब उन्हें माला पहना रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं. समय बदलता है, लेकिन उन्होंने क्या-क्या किया है, यह जनता जानती है. जनता जब इसका मूल्यांकन और फैसला करेगी, वह सही होगा. इसके विपरीत निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? गुजरात के 70 प्रतिशत मकानों को अवैध बताए जाने संबंधी ममता बनर्जी के आरोप पर मंत्री दिलीप घोष ने कहा, क्या वह स्वयं जाकर जांच करके आई हैं कि वे मकान वैध हैं या अवैध? उनके अपने घर ही अवैध हैं-पहले इस बात को ध्यान में रखें.

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक सुधांशु शेखर द्वारा दी इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड, एक्सप्रेस हाउस, एन एच 6 मौजा–प्रशस्थ व अंकुरहाटी,पोस्ट– सलप, थाना–डोमजूर, जिला–हावड़ा–711409 से मुद्रित एवं 19, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट, कोलकाता–700 007 से प्रकाशित. प्रधान संपादक : **सुधांशु शेखर,**
प्रबंध कार्यालय : 19, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट, कोलकाता–700 007, RNI No. WBHIN/2007/22434 फोन : 9831494084, टेलीफैक्स : 22743382 ई–मेल : yuvashakti@hotmail.com प्रकाशन संबंधी समस्त विवादों का निपटारा कोलकाता न्यायालय के अधीन